न्यायधिश सतीश कांतार मित्तल एवं न्यायधीश अमोल रतन सिंह के समक्ष

दीप चंद- अपीलकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य- ऊतरवादी

सिविल रिट याचिका संख्या 670-DB of 2007

जनवरी 11, 2013

भारतीय दंड संहिता,1860- धारा 302, 84 - मानसिक विक्षिप्तता - चिकित्सीय विक्षिप्तता - कानूनी विक्षिप्तता - अपीलकर्ता ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी - विक्षिप्त मानसिक स्थिति का बचाव किया - निचली अदालत द्वारा दोषी करार दिया गया - अपील दायर की - हत्या 17.6.2006 को हुई - डॉक्टर ने बचाव गवाह के रूप में परीक्षण किया - अपीलकर्ता ने स्वीकार किया 13.10.2006 को मनोचिकित्सा वार्ड में - 15.11.2006 को छुट्टी दे दी गई - निदान किया गया कि "लगातार भ्रम संबंधी विकार से पीड़ित होने की संभावना है" - माना गया - चिकित्सीय पागलपन और कानूनी पागलपन के बीच अंतर करना होगा - स्तर ऐसा होना चाहिए जिससे एक व्यक्ति अपनी कार्रवाई के प्रभाव और पीड़ित पर पड़ने वाले परिणामों को समझने में असमर्थ है - आगे कहा गया - साक्ष्यों से यह नहीं पता चला कि वह अपनी कार्रवाई की प्रकृति को समझने में असमर्थ था - धारा 84 1पीसी का लाभ देने से इनकार किया गया - अपील खारिज कर दी गई।

यह निर्धारित किया गया, जो नहीं हो सकता इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि, सभी तीन गवाहों, यानी, अपीलकर्ता के बच्चे (किशोर उम्र के), ने दावा किया है कि जब उन्होंने अपने पिता को अपनी माँ को मारते हुए देखा था, तब उन्होंने उसे जाँचा था, लेकिन इसके बावजूद, उसने उसे बार-बार मारा था। भाग जाओ। इसके बाद, जब मृतक (उनकी मां) का शव पीडब्ल्यू 11 रविंदकर द्वारा घर लाया गया तो उसने उन्हें फिर से धमकी दी थी। जाहिर है, अपीलकर्ता को अपने कृत्य के परिणामों से अनभिज्ञ नहीं कहा जा सकता। मेरा मानना है कि उसके दिमाग की अस्वस्थता या अस्थायी अस्वस्थता के कारण उसे संदेह का लाभ दिया जा सकता है या नहीं, इस मुद्दे पर भारत में कानूनी स्थिति के अनुसार जांच की जाएगी।

(पैरा 25)

आगे माना जाता है कि हालाँकि, भारत में अदालतों ने हमेशा चिकित्सीय पागलपन और कानूनी पागलपन के बीच अंतर किया है, इस आशय के लिए कि, डॉक्टर को जो मानसिक अस्वस्थता लग सकती है, वह ऐसी प्रकृति या स्तर का नहीं हो सकता है कि ऐसा किया जा सके। एक व्यक्ति अपने कार्यों के प्रभावों को समझने में असमर्थ है, ताकि उसे यह जानने के अपराध से मुक्त किया जा सके कि वह क्या कर रहा है, और पीड़ित को उसके परिणाम क्या होंगे।

(पैरा 26)

इसके अलावा, यह माना गया कि इस धारा का लाभ लेने के लिए यह अपवाद है, इसे साबित करना होगा, भले ही सबूत की उतनी ताकत न हो, जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा आवश्यक है, लेकिन फिर भी, अभी भी एक प्रशंसनीय सीमा तक, कि आरोपी अपने कृत्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ था।

(पैरा 33)

आगे कहा गया, कि हमारी सुविचारित राय में, पूरे सबूतों को देखने के बाद, ऐसा कोई संकेत नहीं है, जो भी हो, कि मृतक, जो अपीलकर्ता थे 'पत्नी, किसी भी समय, उसे धमकी देने की स्थिति में थी ताकि उसे विश्वास हो जाए कि वह आत्मरक्षा में काम कर रहा था; वास्तव में, धारा 313 सीआरपीसी के तहत अपने बयान में भी उनके द्वारा ऐसी कोई दलील नहीं दी गई थी, जो उन्हें मुकदमे के लिए फिट घोषित किए जाने के बाद दर्ज किया गया था, भले ही अपराध करने के समय वह किसी भ्रम में थे। उसने उसके चरित्र या भाग्य को किसी भी प्रकार की चोट पहुंचाई थी, या किसी भी तरह से, उसके प्रति दयालु नहीं थी, फिर भी, उसके कृत्य के परिणामों के बारे में जानते हुए भी, मेरे नॉटेन नियमों के अनुसार, वह इसके लिए उत्तरदायी होगा सज़ा. इस प्रकार, चर्चा किए गए कानून के अनुसार, धारा 84 1पीसी का लाभ लेने के लिए, उसे अपनी कार्रवाई की प्रकृति को समझने में पूरी तरह से असमर्थ दिखाना होगा। ट्रायल कोर्ट में पेश किए गए सबूतों के अनुसार, हमारा दृढ़ मत है कि वह ऐसी किसी भी मानसिक स्थिति में नहीं था।

(पैरा 35)

अपीलकर्ता के लिए गुरिंदर सिंह गोराया, वकील।

परमजीत बट्टा, महालेखाकार, हरियाणा।

(1) यह अपील एकमात्र आरोपी दीप चंद द्वारा विद्वान सत्र न्यायाधीश, नामौल, वीडीसी द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 8.6.2007 के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें उन्हें दोषी पाया गया था और धारा 302 आई पीसी के तहत दोषी ठहराया गया था। परिणामस्वरूप, उसे आजीवन कारावास और 5,000/- रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई, जिसका भुगतान न करने पर उसे एक वर्ष के लिए अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ा।

(2)18.6.2006 को पुलिस चौकी, सरकारी अस्पताल, नारनौल के प्रभारी को सूचना प्राप्त हुई कि दीप चंद (अपीलकर्ता) की भगवती पत्नी, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी ओ ('गांव तुर्कियावास, पुलिस स्टेशन ए टेल आई) , को कई चोटों के साथ सरकारी अस्पताल, नारनौल में भर्ती कराया गया है। यह सूचना मिलने पर, एएसआई चंद्र भान (पीडब्ल्यू 13), एक कांस्टेबल जसबीर सिंह के साथ, डॉक्टर से राय लेने के लिए एक आवेदन के साथ सरकारी अस्पताल, नारनौल पहुंचे। घायल भगवती की हालत खराब होने पर डॉक्टर ने लिखा कि उसे पीजीआईएमएस, रोहतक रेफर कर दिया गया है। इसके बाद, एएसआई चंद्रभान, कांस्टेबल राजेश के साथ 19.6.2006 को घायल महिला का बयान दर्ज करने के लिए पीजीआईएमएस, रोहतक पहुंचे। उसी पर डॉक्टर की राय। डॉक्टर ने पुलिस पार्टी के सामने कहा कि एफवीआई हेज तुर्क आईएवास निवासी दीप चंद की पत्नी भगवती को रिकॉर्ड के अनुसार पीजीआईएमएस, रोहतक में भर्ती नहीं किया गया था।

इसके बाद, पुलिस पार्टी पहुंची ग्राम तुर्कियावास निवासी परभाती लाल के पुत्र राम चंद्र लंबरदार से मिले, जिन्होंने अपना बयान दर्ज कराया, जिसे एफआईआर में बदल दिया गया, जिसमें कहा गया कि वह सीआरपीएफ के पेंशनभोगी हैं और गांव के लंबरदार हैं और आज, 19.6.2006 को वह निजी काम से सुबह 5.00 बजे दिल्ली गया था और शाम 6.00 बजे वापस लौटा तो पता चला कि पिछले दिन 17/18.6.2006 की रात को दीप चंद पुत्र 11 एआर दत्त, निवासी ओ (' गांव ढाणी तुर्कियावास ने अपनी पत्नी भगवती को चोट पहुंचाई थी। एक लकड़ी की छड़ी (डंडा) के साथ और घायल महिला को उसके बेटे रविंदक्र (पीडब्ल्यू 11) द्वारा

एटकली और जनरल 1 अस्पताल, नारनौल ले जाया गया, जहां से उसे पीजीआईएमएस, रोहतक रेफर कर दिया गया।

(3)रोहतक के रास्ते पर, चरखी दादरी के पास उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद, उसे वापस लाया गया और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा पुलिस को कोई सूचना दिए बिना रात में लगभग 8/9 बजे गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया। मैंने आगे कहा कि भगवती की मृत्यु उसके पति की चोटों के परिणामस्वरूप हुई थी। मैंने यह भी दर्ज किया कि उसने सुना था कि दीप चंद अपनी पत्नी को पीटता था। भगवती. वह। परिणामस्वरूप, अनुरोध किया गया कि दीप चंद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।

इस व्यक्ति ने बाद में ट्रायल कोर्ट के सामने PW9 के रूप में गवाही दी और कहा कि उसका बयान 20.6.2006 (19.6.2006 नहीं) को दर्ज किया गया था। 1 लोसीवीसीआर. इससे अभियुक्तों के अपराध या अन्यथा के निर्धारण में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं आएगा, जैसा कि बाद में देखा जाएगा।

(4) 'एचआर आगे कहता है कि, एमएलआर दिनांक 18.6.2006 के अनुसार, भगवती को दो चोटें लगी थीं और दोनों को एक्स-रे और सीटी स्कैन की सलाह दी गई थी, और यह एक कुंद हथियार के कारण हुआ था। इसके परिणामस्वरूप, एचआर धारा 302/201/34 आई पीसी के तहत पंजीकृत किया गया था। हालाँकि, विशेष रिपोर्ट इलाका मजिस्ट्रेट आदि को भेज दी गई थी। कहा गया है कि एएसआई चंदर भान (पीडब्लू13) 19.6.2006 को रात 9.15 बजे के बाद घटना स्थल पर पहुँचे थे। हालाँकि 19.6.2006 को फ़ाइल पर कोई आगे की कार्यवाही दर्ज नहीं की गई थी, बाद में, एएसआई चंदर भान (पीडब्ल्यू 13) के बयान में, यह आया कि हालांकि वह 19.6.2006 को घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन कोई स्पॉट निरीक्षण नहीं किया जा सका। चूंकि अंधेरा था और उसके बाद मामले की जांच इंस्पेक्टर रघुबीर सिंह (पीडब्लू14) को सौंप दी गई थी।

(5) एएसआई चंदरभान से केस फाइल मिलने के बाद। लेकिन अंधेरे के कारण कोई स्पॉट निरीक्षण नहीं किया जा सका और यह 20.6.2006 को किया गया था और रफ साइट प्लान (एलएक्स.पीटी) उसी तारीख को तैयार किया गया था। यद्यपि अभियुक्त (अपीलकर्ता दीप चंद) की गिरफ्तारी का कोई ज्ञापन नहीं है, एक लकड़ी के 'किकर' डंडा (छड़ी, एलएक्स.पीएल) की बरामदगी का ज्ञापन इंस्पेक्टर रघुबीर सिंह द्वारा 20.6.2006 को राम चंदर की उपस्थिति में तैयार किया गया था। पीडब्लू8) पुत्र उमराव सिंह, निवासी ग्राम झरोदा, और एक हनुमान पुत्र मारू राम, निवासी ग्राम ग्राम तुर्कियावास, जिसे सील कर दिया गया था, वसूली के गवाह (राम चंदर, पीडब्लू 8) को सौंप दिया गया था।

'इसके बाद, राख और कहा गया है कि मृतक की हड्डियाँ गाँव में दाह संस्कार के स्थान से बरामद की गई थीं, वीआईडीसी रिकवरी मेमो (पूर्व पीएम), जिन्हें सील कर दिया गया था और परभाती लाल (पीडब्लू 9) के बेटे राम चंदर, लंबरदार को सौंप दिया गया था। डंडा (एक्स.पीएल) और राख और हड्डियां (एक्स.पीएम) को बाद में जांच के लिए ईएसएल में भेजा गया था, हालांकि, इस संबंध में प्रयोगशाला द्वारा इस पर कोई ठोस राय नहीं दी गई थी। 'हालांकि, बाद में, ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपने बयान में, जांच अधिकारी (पीडब्लू 14) ने कहा कि उन्होंने 20.6.2006 को गवाहों सुरेश, मनीषा (मृतक के बच्चे) और धरम चंद के बयान दर्ज किए थे, वही सीएसीसी के प्रदर्शित रिकॉर्ड पर नहीं है। केवल अभियुक्त और मृतक के बेटे राव का बयान, दिनांक 6.8.2006 रिकॉर्ड पर है।

(6) इस कथन के अनुसार, उन्होंने पूरे घटना क्रम का वर्णन किया है, जिसमें प्रासंगिक यह है कि, सुबह 4.00 बजे जब वह खेत में सो रहे थे, उनकी बहन मनीषा ने उन्हें जगाया और कहा कि उनके पिता ने उन्हें चोट

पहुँचाई है। उनकी माँ सिर पर डंडा रखकर सो रही थी और उसके बाद भाग गई थी। मैंने आगे बताया कि उसने देखा कि उसकी मां सिर पर चोट लगने के कारण बेहोश हो गई थी, जिस पर वह उसे पीएचसी, अटेली और फिर जनरल 1 अस्पताल, नारनौल ले आया, जहां डॉक्टर ने उसे प्राथमिक उपचार दिया और फिर रेफर कर दिया। चोटों की प्रकृति के कारण, उसे पीजीएमएस, रोहतक में ले जाया गया (1 लिंडी संस्करण में, वह बताता है कि वह अपनी माँ को ऊँट गाड़ी पर इन अस्पतालों में ले गया)। इसके बाद, उन्होंने एक वाहन की व्यवस्था की और जब वह उसके इलाज के लिए पीजी आई एमएस, रोहतक जा रहे थे, तो रास्ते में चरखी दादरी में उसकी मौत हो गई।

इसके बाद, वह उसके शव को वापस अपने ट्यूबवेल में ले आए, जहां वे सभी थे निवास कर रहे थे. अपने बयान में उन्होंने कहा कि उनके पिता भी वहां आए थे और उन्हें बताया गया कि उनकी मां की मौत हो गई है. उनके मुताबिक, उनके पिता ने उन्हें और उनके भाइयों को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने यह बात किसी को बताई तो वह उन्हें भी जान से मार देंगे। इस धमकी के कारण, उन्होंने अपनी माँ की मृत्यु के कारणों का खुलासा नहीं किया, यहाँ तक कि जब गाँव वाले मौत की खबर सुनकर आये। इसके बाद, उन्होंने रात में लगभग 8/9 बजे उनका अंतिम संस्कार किया, यानी आगे कहा कि उनकी कोई गलती नहीं थी और उनकी मां की मृत्यु उनके पिता द्वारा पहुंचाई गई चोटों के कारण हुई थी। इस कथन के अनुसार, उनके पिता पहले भी कई मौकों पर उनकी पिटाई करते थे। यानी यह भी चाहता था कि उसके पिता के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।

(7) ट्रायल कोर्ट के समक्ष उसका बयान धारा 161 या पी.सी. के तहत उसके द्वारा दिए गए बयान से मेल खाता है, इस हद तक कि उसकी बहन ने उसे जगाया था और उसे बताया था कि उनके पिता ने उनकी मां के सिर पर मांडा मारकर उन्हें घायल कर दिया था। चूँकि वह सो रही थी, और उसके बाद भाग गई थी, लेकिन उसके बाद बयान में कुछ विसंगतियाँ थीं, जिसके कारण, वास्तव में, उसे शत्रुतापूर्ण घोषित कर दिया गया था।

ये विसंगतियाँ इस हद तक हैं कि अदालत के सामने उसका बयान यह था कि वह और उसका छोटा भाई, सुरेश, दोनों अपनी माँ को पीएचसीअटेली (ऊँट गाड़ी में) ले गए थे और उसके बाद, वह उसे एक वाहन में जनरल अस्पताल ले गए, नारनौल और फिर पीजीआईएमएस, रोहतक की ओर। कोर्ट के सामने उसने यह भी कहा कि जब वह अपनी मां का शव अपने घर लाया तो उसके पिता और तीन चार अन्य लोग वहां मौजूद थे. उन्होंने आगे कहा कि उनके पिता ने उन्हें धमकी दी (उनके पहले बयान के अनुरूप) और उसके बाद उन्हें एक कमरे में कैद कर दिया (असंगत)। मैंने यह भी कहा कि उसे नहीं पता कि उसकी मां का अंतिम संस्कार कैसे किया गया और किसने किया। इसी के आधार पर उन्हें शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया था। अपनी जिरह में वह उस डॉक्टर का नाम या उस वाहन का नाम या बनावट नहीं बता सका जिससे वह अपनी मां को सामान्य अस्पताल, नारनौल से रोहतक की ओर ले गया था। मैंने जिरह में आगे कहा कि उसकी मां ने उसे अटेली जाते समय बताया था कि उसके पिता ने उसे डंडे से पीटा था। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि वह जानबूझकर दाह संस्कार का सही समय नहीं बता रहे थे।

(8)अधिकांश सामग्री, अभियुक्त-अपीलकर्ता और मृतक की बेटी पीडब्लू10 मनीषा की गवाही है। उसने बताया कि वह 18.6.2006 को सुबह लगभग 4.00 बजे अपने पिता और माँ के बीच झगड़े का शोर सुनकर उठी और उसके पिता दीप चंद ने उसकी माँ के सिर पर डंडा मारा, जो कि सो रही थी। खाट. इसके बाद उसके पिता से पूछने पर उसने उसे चुप रहने की धमकी दी और उसकी मां के सिर पर एक और वार किया और भाग गया। इसके बाद, उसने अपने बड़े भाई रवीन्द्र को बुलाया, जो पास के खेत में सो रहा था और उसे बताया कि उनके

पिता ने उनकी माँ के सिर पर डंडा से हमला किया है। उसके पिता द्वारा और उसके बाद, उनके जागने के बाद उसने एक और डंडा मारा। उसने इस बात से भी साफ तौर पर इनकार किया कि उसकी मां के सिर पर भैंस ने हमला किया था और उसकी वजह से वह गिर गई थी और उसे चोटें आई थीं। उसने इस बात से इनकार किया कि उसके पिता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और उन्होंने उसकी मां को चोट नहीं पहुंचाई थी।

(9) विद्वान लोक अभियोजक (उसे शत्रुतापूर्ण घोषित किए जाने के बाद) और अभियुक्त के लिए विद्वान वकील द्वारा की गई जिरह पर यहां फिर से चर्चा की जा सकती है। पहली जिरह में, उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने पुलिस को बताया था कि उनकी मां का अंतिम संस्कार रात 8.00 से 9.00 बजे के बीच किया गया था, हालांकि उनका बयान (एक्स.पीएन) दर्ज किया गया था।

उनकी जिरह में दूसरी विसंगति इस संबंध में सामने आई तथ्य यह है कि हालाँकि उसने शुरू में पुलिस के सामने कहा था कि उसकी माँ बेहोश थी, अदालत के सामने उसने कहा कि वह उस समय होश में थी जब उसकी बहन ने उसे बुलाया था और उसने एटक्लि के रास्ते में भी उसे बताया था कि उसकी पापा ने उसे डंडा मारा था. उन्होंने अपनी जिरह में यह भी खुलासा किया कि उनकी मां को लगभग एक घंटे तक सीएल आईसी, एटकली में रखा गया था और प्राथमिक उपचार के बाद, वह उन्हें जनरल आई हॉस्पिटल, मानौल ले आए, जहां वह लगभग ढाई घंटे तक भर्ती रहीं। (10) पी. डब्लू 12 सुरेश अपीलकर्ता और मृतक का छोटा बेटा है। यानी भौतिक रूप से घटना के संबंध में अपने अन्य दो भाई-बहनों (पीडब्लू 10 और पीडब्लू 11) के समान ही संस्करण दिया, सिवाय इसके कि उन्होंने अपराध के हथियार को 'डंडा' के बजाय 'लाठी' बताया। 1 यानी उसने यह भी कहा कि उसने अपने भाई रवीन्द्र को बुलाया, जिसने उनके पिता की जाँच की लेकिन उसके बाद फिर से, उनके पिता ने उनकी माँ के सिर पर एक और वार किया और भाग गए। 1 यानि कि वह अपने भाई के साथ उनकी मां को एटकली स्थित क्लिनिक में ले गया। इसके बाद वह घर लौट आये. शाम को उसका भाई अपनी मां का शव घर ले आया। उसने दोहराया कि उसकी माँ की मृत्यु उसके पिता द्वारा दी गई लाठियों के कारण हुई थी। अपनी जिरह में, उसने कहा कि उसकी माँ घटना के बाद एटकली पहुँचने तक बेहोश रही। यानी इस बात से इनकार किया कि उसे भैंस ने टक्कर मार दी थी और उसी के कारण उसे चोटें आई थीं।

(11) ट्रायल कोर्ट के समक्ष अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षण किए गए अन्य महत्वपूर्ण गवाह डॉ. संजय विश्नोई (पीडब्लू1) थे, जिन्होंने इस बात की गंभीरता से पुष्टि की कि उन्होंने 18.6.2006 को अभियुक्त की मृत भगवती पत्नी की चिकित्सकीय रूप से कानूनी जांच की थी और उस पर दो चोटें पाई थीं। व्यक्ति को अंडरसीआर के रूप में वर्णित किया गया है:-

(1)16 ईएमएस x 12 ईएमएस विशाल नील लाल रंग का, दाहिने टेम्पोरल, पार्श्विका पर स्थित है। खोपड़ी, दाहिनी आंख और दाहिनी ओर का आयरनलाल क्षेत्र मध्य रेखा के पार्श्व से 3 ईएमएस है।

(2) 6 ईएमएस गोल नील लाल रंग का, छाती के बाईं ओर के ऊपरी भाग पर स्थित है। मध्य रेखा से 6 ईएमएस पार्श्व और बायीं हंसली से 1 सेमी नीचे। एमएलआर के अनुसार, जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं। मैंने आगे बताया कि 7.8.2006 को, पुलिस ने एक डंडा पेश किया था और संभवतः उसके कारण होने वाली चोटों के संबंध में उनकी राय मांगी थी। 11 सी ने इस आशय की सकारात्मक राय दी उक्त छड़ी से चोट लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। 1 यानी अदालत में उसे दिखाई गई लकड़ी की छड़ी वही थी जो 7.8.2006 को पुलिस द्वारा उसे दिखाई गई थी। अपने क्रॉस में- जांच में, उन्होंने कहा कि किसी जानवर के प्रहार से चोटें लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है और छत आदि से गिरने के कारण चोटें लगने की भी संभावना हो सकती है।

(12)पीडब्लू4, जे आईसीअमरदीप ने गवाही दी कि 20.6.2006 को उन्हें पीडब्लू14 इंस्पेक्टर/एसआई आईओ रघुबीर सिंह ने गांव के श्मशान घाट पर जाकर तस्वीरें लेने के लिए कहा था और उन्होंने ऐसा किया था। हालाँकि उन्होंने इन्हें स्वयं विकसित नहीं किया था, लेकिन मेसर्स तरूण लैब से इन्हें विकसित करवाया था। लगभग 9.00 बजे उक्त गांव में पहुंचे थे और उनकी उपस्थिति में अपीलकर्ता के घर से लकड़ी की छड़ी (डंडा) बरामद की गई थी और उस रिकवरी मेमो (Lx.PL) को जे लानुमन के साथ उनके द्वारा सत्यापित किया गया था। उसकी जिरह से कुछ भी नकारात्मक पता नहीं चला।

(13) पीडब्लू8, उमराव का बेटा राम चंदर, रविंदकर (पीडब्ल्यू11) और पीडब्लू 10 और 12 का चाचा है। उसने गवाही दी कि 19.6.2006 को उसके भतीजे रविंदसीआर ने उसे टेलीफोन पर बुलाया था और वह उक्त तक पहुंच गया था। लगभग 9.00 बजे सुबह गांव पहुंचे और उनकी उपस्थिति में अपीलकर्ता के घर से लकड़ी की छड़ी (डंडा) बरामद की गई और उस रिकवरी मेमो (Lx.PL) को जे लानुमन के साथ उनके द्वारा सत्यापित किया गया। उनसे जिरह में कुछ भी नकारात्मक बात सामने नहीं आई।

(14)शिकायतकर्ता, यानी, राम चंदर, लंबरदार (पीडब्लू9) ने भी गवाही दी और घटना के अपने संस्करण को दोहराया, जैसा कि उनके द्वारा 19.6.2006.1 को दर्ज की गई शिकायत के अनुसार किया गया था, यानी श्मशान घाट से राख और हड्डियों (एक्स.पीएम) की बरामदगी भी साबित हुई। 1 यानी उसने कहा कि उसने अपीलकर्ता द्वारा अपनी पत्नी भगवती को अक्सर पीटने के बारे में सुना था, हालांकि अपनी जिरह में उसने कहा कि उसे ऐसी कोई शिकायत नहीं दी गई थी।

(15)सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपने बयान में, आरोपी ने यह कहने के अलावा कि वह इस मामले में गलत तरीके से शामिल था, अपने पक्ष में कोई ठोस रुख नहीं बताया, हालांकि उसने कहा कि वह अपने बचाव में सबूत पेश करेगा। .

(16)टीएन अदालत के समक्ष बचाव में, डॉ. आईइतेश खुराना, रीडर, मनोचिकित्सा विभाग, पीजी1एमएस, रोहतक से डीडब्ल्यूआई के रूप में जांच की गई। 1 यानी कहा गया कि अपीलकर्ता को 13.10.2006 को पीजीआईएमएस, रोहतक के मनोचिकित्सा वार्ड में भर्ती कराया गया था और 15.11.2006 को छुट्टी दे दी गई थी। मैंने आगे कहा कि वह मेडिकल बोर्ड के सदस्यों में से एक थे, जिन्होंने क्रमशः 8.2.2007 और 12.2.2007 (एक्स.डीसी और एक्स.डीडी) की रिपोर्ट दी थी। अंतिम रिपोर्ट (Ex.DD) के अनुसार, दीप चंद मानसिक रूप से स्वस्थ थे और कोई बाधा नहीं थी और उनका संज्ञान स्तर ठीक था।

Ex. डीए दिनांक 15.11.2006 की रिपोर्ट है जिसके द्वारा, दीप चंद को 'लगातार भ्रम विकार से पीड़ित होने की संभावना' के रूप में निदान किया गया था। कुछ दवाएँ भी निर्धारित की गईं और अनुवर्ती कार्रवाई की सलाह दी गई। आई-ले को 16.11.2006 को एंटी साइकोटिक दवा पर दो सप्ताह के बाद मनोचिकित्सा ओपीडी में अनुवर्ती कार्रवाई की सलाह के साथ छुट्टी दे दी गई, हालांकि उन्होंने 11.12.2006 तक रिपोर्ट नहीं की। रिपोर्ट की तारीख (Ex.DB).

Ex. डीसी और पूर्व. डीडी में वही रिपोर्टें हैं, एक पंजीकृत डाक से और दूसरी स्पीड पोस्ट से प्राप्त हुई, जहां फिर से अपीलकर्ता को लगातार भ्रम विकार से पीड़ित बताया गया। यह कहा गया था कि 'उन्हें निर्धारित उपचार से राहत मिली है और वर्तमान में उनके पास कोई मनोविकृति नहीं है।' यह भी कहा गया कि उसे मुकदमे में खड़े होने के लिए जलाया जाएगा, लेकिन दवा जारी रखने की सलाह दी गई।

इस गवाह के अनुसार, यह कहना संभव नहीं है कि उपरोक्त बीमारी (पर्सिस्टेंट डिल्यूज़नल डिसऑर्डर) कब विकसित होती है, लेकिन यह केवल वयस्कों में विकसित होती है, वयस्कों में नहीं। बच्चे। डॉक्टर ने आगे कहा कि वह मोदी के मेडिकल न्यायशास्त्र और विष विज्ञान (21वें संस्करण) के पृष्ठ 449, पैरा 11 पर दी गई टिप्पणियों से सहमत हैं, जो ऐसे हैं:-

"11 भ्रम: एक गलत धारणा या गलत विश्वास, विपरीत सबूतों के सामने, तर्क या तर्क की अपील द्वारा दृढ़ विश्वास और अपरिवर्तनीय उत्तरदायी माना जाता है जो समान धार्मिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के लिए स्वीकार्य होगा।

भ्रम भव्यता या उच्चता का, संदेह का, अवसाद का, संदर्भ का, ईर्ष्या का और बेवफाई का हो सकता है। भव्यता का भ्रम और उत्पीड़न का भ्रम अक्सर एक ही व्यक्ति में एक साथ होते हैं। उदाहरण के लिए, एक आदमी जो खुद को बहुत अमीर होने की कल्पना करता है, वह यह भी सोच सकता है कि उसके दुश्मन उसे आर्थिक रूप से बर्बाद करने की साजिश रच रहे हैं।

भ्रम चिकित्सा-कानूनी दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे अक्सर आचरण और कार्रवाई को प्रभावित करते हैं पीड़ित, और उसे आत्महत्या, हत्या या किसी अन्य अपराध के लिए प्रेरित कर सकता है। न्यायाधीश और वकील पागलपन के लक्षण के रूप में भ्रम की उपस्थिति को बहुत महत्व देते हैं। मेरा मानना है कि एक चिकित्सक के लिए यह आवश्यक है कि वह परीक्षा के दौरान उत्पन्न होने वाले किसी भी भ्रम को सावधानीपूर्वक नोट कर ले। रोगी दीप चंद को यह रोग कब प्रकट हुआ होगा, या यह रोग कब शुरू हुआ था। हालांकि उसने कहा कि यह निश्चित है कि यह रोग कभी अचानक प्रकट नहीं होता। एक बार रोगी ठीक हो जाए तो उसे यह रोग दोबारा भी नहीं हो सकता है।

(17)डीडब्ल्यू2 डॉ.ओ.पी.सरोवा, चिकित्सा अधिकारी, जिला जेल, नारनौल ने बताया कि अपीलकर्ता को अदालत के आदेश दिनांक 6.8.2006 के अनुसार पीजी आईएमएस, रोहतक में इलाज के लिए जिला जेल, रोहतक में स्थानांतरित कर दिया गया था। उन्होंने अपनी जिरह में यह भी कहा कि, रिपोर्ट (एक्स.डीएफ) के अनुसार, उनकी (अपीलकर्ताओं की) मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और इसीलिए, उन्हें बाद में पीजी आई एमएस, रोहतक रेफर किया गया था।

एक्स. डीएफ चिकित्सा अधिकारी, जिला जेल, नारनौल द्वारा अधीक्षक, जिला जेल, नारनौल को संबोधित पत्र है, जिसमें कहा गया है कि अपीलकर्ता सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है। पत्र में आगे कहा गया है कि यद्यपि वह जिला जेल, नारनौल और सरकारी अस्पताल, नारनौल में इलाज करा रहा था, लेकिन उसे पर्याप्त प्रतिक्रिया नहीं मिल रही थी और चूंकि जिला मोहिंदरगढ़ में कोई मनोचिकित्सक नहीं है, इसलिए उसे जिला जेल, रोहतक में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

(18) हमने अपीलकर्ता की ओर से श्री गुरिंदर सिंह गोराया (कानूनी सहायता सेल के माध्यम से उपस्थित विद्वान वकील) और प्रतिवादी की ओर से श्री परमजेक्ट बत्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा को सुना है।

(19) अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने हमारे सामने महत्वपूर्ण गवाहों के बयानों में विसंगतियों को उजागर किया, अर्थात् मृतक और अपीलकर्ता के तीन बच्चे, अर्थात् मनीषा (पीडब्लू10), रवीन्द्र (पीडब्लू11) और सुरेश (पीडब्लू12)

और प्रस्तुत किया कि विसंगतियों को देखते हुए, भगवती की मृत्यु अपीलकर्ता द्वारा दिए गए किसी भी प्रहार के कारण नहीं हुई, बल्कि अन्य कारणों से उन्हें लगी चोटों का परिणाम थी, जैसे कि भैंस के टकराने के कारण गिरना।

हम इस तर्क में कोई योग्यता नहीं पाते हैं, और इसे खारिज करते हैं, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि, हालांकि तीन बच्चों के बयानों में कुछ हद तक विसंगतियां थीं, जबकि पीडब्लू 10 ने पहले कहा था कि जब उसकी मां खाट पर सो रही थी तो उसके पिता ने उसके सिर पर एक डंडा मारा और जब उसने कारण पूछा तो उसने उसे धमकाया और उसकी मां के सिर पर एक और वार किया और भाग गया; जिरह के दौरान उसने कहा गया कि पहला झटका उसके उठने से पहले ही दिया जा चुका था और दूसरा झटका उसके (पीडब्ल्यू10) जागने के बाद दिया गया था। जिरह में, उसने आगे कहा कि जब उसे ऊंट गाड़ी पर अटेली ले जाया गया, तो उसका भाई सुरेश भी उसकी मां और उसके बड़े भाई रविंदक्र के साथ गया था। उनकी मां अटेली गईं, जबकि सीआरपीसी की धारा 161 के तहत अपने बयान में उन्होंने यह उल्लेख नहीं किया कि सुरेश उनके साथ अटेली गया था। कि वह और उसका भाई दोनों अपनी माँ को एटक्लि ले गये थे। इसके अलावा, रवीन्द्र ने पुलिस के समक्ष अपने बयान में कहा था कि कुछ ग्रामीण शाम को उनकी मां के शव को वापस लाने के बाद एकत्र हुए थे, लेकिन उनके पिता द्वारा सभी को दी गई धमकी के कारण मौत के कारण का खुलासा नहीं किया गया था। बच्चे। मैंने आगे कहा था कि उनकी मां का अंतिम संस्कार रात में लगभग 8/9 बजे किया गया था। दूसरी ओर, ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपनी गवाही में, उसने कहा कि उसके पिता ने उसे धमकी दी थी और एक कमरे में बंद कर दिया था और उसके बाद क्या हुआ उसे नहीं पता। 1 यानी यह बताने से भी इनकार किया कि उनकी मां का अंतिम संस्कार रात 8-9.00 बजे किया गया था। इसके अलावा, जिरह में, उसने यह भी कहा था कि अटेली के रास्ते में उसकी माँ होश में थी और उसने उसे यह भी बताया था कि उसके पिता ने उसे 'डंडा' मारा था। दूसरी ओर, सुरेश ने विशेष रूप से कहा कि उसकी मां अटेली पहुंचने तक चोटें लगने के बाद बेहोश रही थीं।

(20) हमारी राय में, ये विसंगतियां ऐसी प्रकृति की नहीं हैं जो अभियोजन मामले के लिए घातक हों। पीडब्लू10 मनीषा के जागने के बाद एक स्थान या अन्य स्थान की विसंगतियों के संबंध में, हमारी राय में यह है इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सुबह 4.00 बजे घटनाओं का सटीक क्रम उसके दिमाग में स्पष्ट नहीं हो सकता है, यह बहुत छोटी विसंगति है। मैं देखता हूं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने और उसके भाई दोनों ने कहा है कि उनके पिता उनकी मां के सिर पर छड़ी से वार कर रहे हैं। इसलिए, हमें घटना के बारे में कोई घातक विसंगति नहीं मिली।

जहां तक दाह संस्कार के समय और तरीके का संबंध है। संभवतः, इन तीनों गवाहों, अर्थात्, मृतक और अपीलकर्ता के बच्चों, मनीषा, रवीन्द्र और सुरेश को पता चल गया था कि पुलिस को सूचित किए बिना या सबूतों को इस हद तक नष्ट करने के लिए उन पर धारा 201 1PC के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। उनकी मां के शव का पोस्टमॉर्टम किया गया, उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया था/करवाया गया था। 'इसलिए, किसी

भी दोषारोपण से बचने के लिए, उन्होंने दाह संस्कार के संबंध में कुछ अलग-अलग संस्करण दिए थे, जो, हमारी राय में, किसी भी तरह से, अपीलकर्ता को अपनी पत्नी के सिर पर डंडों से वार करने के अपराध से मुक्त नहीं करते हैं। उसकी बाद की मृत्यु के लिए।

(21)वास्तव में, उन तीनों बच्चों के लिए, जो उस समय सुरेश के मामले में वयस्क या शायद 18 वर्ष से थोड़ा कम उम्र के बताए गए थे, कोई भी कारण नहीं है। अपने ही पिता के ख़िलाफ़ झूठी गवाही देना, जबकि उनके और उनके बीच किसी दुश्मनी का दूर-दूर तक कोई संकेत नहीं है। रवीन्द्र के बयान में इस हद तक सुधार हुआ कि उनकी मां ने उन्हें अटेली जाते समय बताया था कि उनके पिता ने उन्हें डंडा मारा था, जाहिर है, यह सुनिश्चित करने के लिए ही किया गया था कि उनके पिता किसी भी बहाने से अपराध बोध से बच न जाएं। उसकी माँ को मार डाला. चूँकि वह अपने पिता द्वारा अपनी माँ के सिर पर डंडा से किए गए वार की वास्तविक घटना का चश्मदीद गवाह नहीं था, इसलिए उसके भाई और बहन ने जो देखा उसे दोहराने के लिए अपने बयान में सुधार करने की संभावना को स्पष्ट रूप से खारिज नहीं किया जा सकता है। मैं उनके बेहतर बयान को नजरअंदाज करते हुए भी, उनके भाई और बहन द्वारा दिए गए प्रत्यक्षदर्शी बयान को नजरअंदाज करता हूं, जिन्होंने वास्तव में एक व्यक्ति को अपनी मां को 'डंडा' से मारते और फिर भागते हुए देखा था, और फिर तीनों बच्चों द्वारा उन्हें दी गई धमकी की पुष्टि की गई थी। अपने पिता द्वारा सहजता से उन्होंने उस घटना का खुलासा कर दिया जिसके कारण उनकी माँ की मृत्यु हो गई, हमारे मन में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रह गया, कि यह वह व्यक्ति है जिसने अपनी पत्नी पर 'डंडा' मारा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मुकदमे के दौरान एक भैंस का परिचय देना, जिसने मृतक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई, यह बहुत स्पष्ट भ्रम है, जिसका कहीं से भी अस्पष्ट संकेत नहीं मिलता है।

(22) मेडिको लीगल रिपोर्ट में व्यक्ति पर दो चोटें दिखाई गई हैं मृतक का, जिसका वर्णन पहले ही ऊपर किया जा चुका है। बताया गया है कि दोनों चोटें एमएलआर में किसी कुंद हथियार से लगी थीं। जाहिर है, लकड़ी का 'डंडा'/'लाठी' एक कुंद हथियार है और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अभाव में भी, हमारा मानना है कि चश्मदीद गवाहों, जो अपीलकर्ताओं के अपने बच्चे हैं, की गवाही के साथ-साथ मेडिको लीगल रिपोर्ट भी शामिल है। कि यह अपीलकर्ता ही है जिसने ऊपर बताए गए तरीके से अपनी पत्नी को चोटें पहुंचाईं, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।

(23) अपीलकर्ता के विद्वान वकील का अगला तर्क यह था कि अपीलकर्ता एक मानसिक बीमारी से पीड़ित था, जिसके कारण वह अपने कार्यों की प्रकृति को समझने में असमर्थ था और इस तरह, उसे आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। इस संबंध में, उन्होंने डीडब्ल्यूएल डॉ. हितेश खुराना की गवाही के रूप में चिकित्सा साक्ष्य के साथ-साथ अपीलकर्ता, आईसी, पूर्व के संबंध में चिकित्सा रिपोर्ट पर भी भरोसा किया है।

(24)भ्रम के संबंध में मोदी की टिप्पणी है कि वे अक्सर पीड़ित के आचरण और कार्य को प्रभावित करते हैं, और उसे आत्महत्या, हत्या या किसी अन्य अपराध के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तत्काल प्रभाव से, पीजी1एमएस, रोबटैक के मेडिकल बोर्ड द्वारा अपीलकर्ता को पर्सिस्टेंट डिल्यूजनल डिसऑर्डर से पीड़ित पाया गया। जाहिर है,

ऐसी रिपोर्टों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और उन्हें उचित महत्व दिया जाना चाहिए और चेतावनी दी जानी चाहिए।

(25) पीडब्लू9 लंबरदार राम चंदर, शिकायतकर्ता और सरपंच के पति ग्राम सलीमपुर तुर्कियावास ने जिरह में कहा कि वह दीपचंद की मानसिक स्थिति के बारे में नहीं कह सकते। अपीलकर्ता की बेटी पीडब्लू10 मनीषा ने अपनी जिरह में कहा कि यह कहना गलत है कि उसके पिता स्वस्थ दिमाग के नहीं हैं। अपीलकर्ता के बेटे पीडब्लू 11 रविंदर ने अपनी मुख्य जांच और जिरह में अपने पिता की मानसिक स्थिति के संबंध में कुछ भी नहीं बताया है। पीडब्लू 12 अपीलकर्ता के एक अन्य बेटे सुरेश ने भी अपनी जिरह में कहा कि यह कहना गलत है कि उसके पिता एक विकृत दिमाग के व्यक्ति थे। पीडब्लू I 0,11 और 12 ने भी जिरह में कहा कि उन्हें पता है कि दीप चंद मानसिक रूप से विक्षिप्त है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वह स्पष्ट रूप से पीडब्लू 10, 11 और 12 का मामा नहीं है, बल्कि पैतृक पक्ष से एक रिश्तेदार है, क्योंकि उसने अपनी गवाही में पीडब्लू 11 को अपना 1 भतीजा कहा था, न कि 'भांजा'। हालाँकि, माता-पिता के आधार पर, वह स्पष्ट रूप से आरोपी का सगा भाई नहीं है।

जो बात नज़रअंदाज नहीं की जा सकती वह यह है कि, सभी तीन गवाहों, यानी, अपीलकर्ता (अक्सर उम्र के) के बच्चों ने कहा है कि उन्होंने अपनी जाँच की थी पिता ने जब उसे अपनी माँ को मारते हुए देखा, लेकिन इसके बावजूद, उसने उसे फिर से मारा और फिर भाग गया। इसके बाद, जब पीडब्ल्यू 11 रविंदर द्वारा मृतक (उनकी मां) का शव घर लाया गया तो उसने उन्हें फिर से धमकी दी थी। जाहिर है, अपीलकर्ता को अपने कृत्य के परिणामों से अनभिज्ञ नहीं कहा जा सकता। हालाँकि, उसके दिमाग की अस्वस्थता या अस्थायी अस्वस्थता के कारण उसे संदेह का लाभ दिया जा सकता है या नहीं, इस मुद्दे पर भारत में कानूनी स्थिति के अनुसार जांच की जानी है।

(26) इसलिए, सवाल यह है कि क्या इस तथ्य के आलोक में कि अपीलकर्ता को लगातार भ्रम विकार का निदान किया गया है, क्या वह भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के लाभ का हकदार है, जिसे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

" 84. विकृतबुद्धि व्यक्ति का कृत्य - कोई भी कार्य अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो ऐसा करते समय, विकृतबुद्धि के कारण यह जानने में असमर्थ हो कि उस कार्य की प्रकृति क्या है या वह क्या कर रहा है। जो या तो गलत है या कानून के विपरीत है।"

इसमें कोई संदेह नहीं है, जैसा कि मोदी ने बीमारी के प्रभावों के बारे में बताया है, यह इस हद तक है कि यह "अक्सर पीड़ित के आचरण और कार्यों को प्रभावित करता है और उसे आत्महत्या, हत्या या किसी अन्य अपराध के लिए प्रेरित कर सकता है"। भारत में अदालतों ने हमेशा चिकित्सीय पागलपन और कानूनी पागलपन के बीच अंतर किया है, इस आशय से कि, जिसे डॉक्टर मानसिक रूप से अस्वस्थता मान सकता है, वह ऐसी प्रकृति या

स्तर का नहीं हो सकता है कि कोई व्यक्ति समझने में असमर्थ हो जाए। उसके कार्य के प्रभाव, ताकि उसे यह जानने के अपराध से मुक्त किया जा सके कि वह क्या कर रहा है, और पीड़ित पर उसके परिणाम क्या होंगे।

(27) इस संबंध में इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख किया जा सकता है, जैसा कि आगे चर्चा की गई है:-

(i) श्रीकांत आनंद राव भोंसले बनाम महाराष्ट्र राज्य में मानसिक अस्वस्थता की दलील को बरकरार रखते हुए एक मामले में (!), सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार कहा:-

18. हम पहले ही देख चुके हैं कि घटना से पहले और घटना के बाद मन की अस्वस्थता सिद्ध होती है। राज्य के विद्वान वकील द्वारा इस पर उचित रूप से सवाल नहीं उठाया गया है। अपराध के समय अभियुक्त की मानसिक स्थिति के संबंध में, हमारी राय में, आमतौर पर यह परिस्थितियों से अनुमान लगाया जाने वाला एक पहलू होगा, इसके अलावा, जैसा कि पहले देखा गया है, अभियुक्त पर सबूत के बोझ की प्रकृति है इससे अधिक कुछ नहीं जो सिविल कार्यवाही में किसी पक्ष पर निर्भर करता है।

19.जो परिस्थितियाँ हाथ में आसानी से साबित होती हैं वे इस प्रकार हैं:

1.अपीलकर्ता का पारिवारिक इतिहास है क्योंकि उसके पिता मानसिक बीमारी से पीड़ित थे।

2.बीमारी का कारण ज्ञात नहीं है - वंशानुगत एक भूमिका निभाता है।

3.अपीलकर्ता का 1992 से मानसिक अस्वस्थता का इलाज किया जा रहा था, पता चला कि वह पैरानॉयड सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है।

4.थोड़े समय के भीतर, 27 तारीख की घटना के तुरंत बाद जून से 5 दिसंबर तक. 1994 में उन्हें 25 लाइम्स की बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा।

5.अपीलकर्ता की मानसिक बीमारी का नियमित इलाज चल रहा था।

6.पत्नी की हत्या का कमजोर मकसद यह था कि वह अपीलकर्ता द्वारा पुलिस कांस्टेबल की नौकरी से इस्तीफा देने के विचार का विरोध कर रही थी।

7.दिन में हत्या छिपने या भागने का कोई प्रयास न करें।

20.श्रीमान अरुण पेडनेकर श्रक्रल्ली वली मोहम्मद बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र [(1973) 4 एससीसी 791')पर भरोसा करते हुए कहते हैं कि यह केवल तथ्य है कि अपीलकर्ता ने भागने का कोई प्रयास नहीं किया या उसने दिन के उजाले में अपराध किया और कोशिश नहीं की। इसे छिपाने के लिए या कि उसकी पत्नी को मारने का मकसद बहुत कमजोर था, यह इंगित नहीं करेगा कि कृत्य के समय अपीलकर्ता मानसिक रूप से अस्वस्थता से

पीड़ित था या उसके पास अपराध करने के लिए अपेक्षित मेन्स रीया नहीं था। यह सही है कि ये तथ्य स्वयं पागलपन का संकेत नहीं देंगे। हालाँकि, वर्तमान मामले में, यह न केवल उपरोक्त तथ्य हैं, बल्कि यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के आलोक में देखी गई परिस्थितियों की समग्रता है कि अपीलकर्ता पैरानॉयड सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित था। 'अर्थात् घटना से पहले और बाद में मानसिक अस्वस्थता एक प्रासंगिक तथ्य है, मामले की परिस्थितियों से स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अपीलकर्ता प्रासंगिक समय पर भ्रम में था। वह किसी बीमारी के आक्रमण में था। 'क्रोध सिद्धांत जिस पर भरोसा किया गया है उसे सिज़ोफ्रेनिया हमले के तहत खारिज नहीं किया जाता है। अपीलकर्ता पर बोझ की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि अपीलकर्ता ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 के अनुसार आवश्यक परिस्थितियों के अस्तित्व को साबित कर दिया है ताकि धारा 84 जे पीसी का लाभ प्राप्त किया जा सके। हम यह मानने में असमर्थ हैं कि अपराध अत्यधिक क्रोध के परिणामस्वरूप किया गया था। 'यहां एक उचित संदेह है कि अपराध के समय, अपीलकर्ता मानसिक अस्वस्थता के कारण कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ था और इस प्रकार, वह धारा 84 आई पीसी के लाभ का हकदार है। अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सजा को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

दूसरी ओर, फैसले में बचाव पक्ष की याचिका को धारा 84 आई पी सी के तहत इस प्रकार खारिज कर दिया गया है:-

(ii) राजस्थान राज्य बनाम शेरा रांट (ए) विष्णु दत्त, जिसमें इस प्रकार चर्चा की गई थी:-

“17. एक आपराधिक अपराध करने के लिए, आम तौर पर मेंस रीया को अपराध का एक अनिवार्य तत्व माना जाता है। ऐसा कहा जाता है फ्यूरियसस नल्ला वोलुंटास सीएसट, दूसरे शब्दों में, एक व्यक्ति जो मानसिक विकार से ग्रस्त है, उसे अपराध करने वाला नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह नहीं जानता कि वह क्या कर रहा है। अपराध करने के लिए इरादा और कार्य दोनों को अपराध का घटक माना जाता है। अपराध, एक्टस नॉन फेसिट आरसीम निसी मेन्स सिट आरसीए। प्रत्येक सामान्य और समझदार इंसान से अपेक्षा की जाती है कि उसके पास अपने आचरण और कृत्यों के लिए जिम्मेदार होने के लिए कुछ हद तक कारण हो, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो। लेकिन एक विकृत दिमाग वाला व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति मानसिक विकार से मानव व्यवहार के इस बुनियादी मानदंड को धारण करने वाला नहीं कहा जा सकता है।

18.सुरेंद्र मिश्रा बनाम झारखंड राज्य में, अदालत एक सहजता से निपट रही थी जहां आरोपी पर धारा 302 आई पीसी और धारा 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था। आरोपी को आईपीसी की धारा 84 के संरक्षण से इनकार करते हुए, न्यायालय ने निम्नानुसार कहा: (एससीसी पीपी.499-500, पैरा 11)

" 11. हमारी राय में, एक आरोपी जो दायित्व से छूट चाहता है भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के तहत एक अधिनियम कानूनी पागलपन साबित करना है न कि चिकित्सीय पागलपन। भारतीय दंड संहिता में "मन की अस्वस्थता" अभिव्यक्ति को परिभाषित नहीं किया गया है और इसे मुख्य रूप से पागलपन के बराबर माना गया

है। लेकिन पागलपन शब्द अलग-अलग संदर्भों में अलग-अलग अर्थ रखता है और मानसिक विकार की अलग-अलग डिग्री का वर्णन करता है, मानसिक रोग से पीड़ित जीवंत व्यक्ति को वास्तव में आपराधिक दायित्व से छूट नहीं है। केवल तथ्य यह है कि अभियुक्त घमंडी, अजीब, चिड़चिड़ा है और उसका दिमाग बिल्कुल ठीक नहीं है, या जिन शारीरिक और मानसिक रोगों से वह पीड़ित है, उसने उसकी बुद्धि को कमजोर कर दिया है और उसकी भावनाओं को प्रभावित किया है या कुछ असामान्य कृत्यों में लिप्त है, या थोड़े-थोड़े अंतराल पर पागलपन के दौरे पड़ते थे या उसे मिर्गी के दौरे आते थे और असामान्य व्यवहार था या व्यवहार अजीब था, जो दंड संहिता की धारा 84 के आवेदन को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

19.उपर्युक्त सिद्धांतों से, यह स्पष्ट है कि किसी भी मानसिक विकार से पीड़ित होने का आरोप लगाने वाले व्यक्ति को वास्तव में आपराधिक दायित्व से छूट नहीं दी जा सकती है। आरोपी पर विशेषज्ञ साक्ष्य द्वारा यह साबित करने का दायित्व होगा कि वह इस तरह के मानसिक विकार से पीड़ित है। एक मानसिक विकार या मानसिक स्थिति जिसके कारण उससे अपने कृत्य के परिणामों के बारे में जागरूक होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। एक बार, कोई व्यक्ति मानसिक विकार या मानसिक विकार से पीड़ित पाया जाता है, जो उचित दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य के माध्यम से सभी प्रासंगिक समयों में मतिभ्रम, मनोभ्रंश, स्मृति और आत्म-नियंत्रण की हानि को अपने दायरे में लेता है, तो संबंधित व्यक्ति को दोषी ठहराया जाएगा। आपराधिक दायित्व से सामान्य अपवादों का सहारा लेने का हकदार।

(iii) टी.एन. लक्ष्मैया बनाम कर्नाटक राज्य[1] (3), जिसमें दंड संहिता के अध्याय IV में दिए गए सामान्य अपवाद में धारा 84 को शामिल किए जाने की पृष्ठभूमि पर चर्चा के बाद, इसे निम्नानुसार देखा गया: -

“8. अध्याय में सन्निहित सिद्धांत कहावत एक्टस नॉन फैसिट आरकम, निसी मेन्स सिट रीई पर आधारित है। कोई कार्य तब तक आपराधिक नहीं है जब तक कि उसका आपराधिक इरादा न हो।

9 एवम 10 x x x x x

11. आसानी से जहां भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के तहत अपवाद का दावा किया जाता है, अदालत को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या अपराध के समय, मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण अभियुक्त, कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ था। या कि वह जो कर रहा है वह या तो कानून के विपरीत गलत है। अपराध करने के समय से लेकर सत्र की कार्यवाही शुरू होने तक अभियुक्त का संपूर्ण आचरण, यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रासंगिक है कि उठाई गई याचिका वास्तविक थी, प्रामाणिक थी या बाद में सोची गई थी।"

(iv) फिर से बापू @गुजराज सिंह बनाम राजस्थान राज्य[2] (4) में यह निर्धारित गया:-

“11. धारा में ही प्रावधान है कि लाभ तभी मिलेगा जब यह साबित हो जाए कि कृत्य करते समय अभियुक्त था

---

[1] (2002)1SCC 219
[2] (2007) 8 SCC 66

मन की बीमारी से, तर्क के ऐसे दोष के तहत काम करना, जैसे कि वह जो कार्य कर रहा था उसकी प्रकृति और गुणवत्ता को नहीं जानता था, या भले ही वह इसे नहीं जानता था, यह या तो गलत था या कानून के विपरीत था तो यह धारा लागू किया जाना चाहिए. इस धारा का लाभ दिया जाना चाहिए या नहीं, यह तय करने के लिए महत्वपूर्ण समय वह समय है जब अपराध घटित होता है। उस निष्कर्ष पर पहुंचने में, प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, केवल अपराध के चरित्र से प्राप्त तर्कों पर पागलपन की रक्षा को स्वीकार करना खतरनाक होगा। यह केवल मन की अस्वस्थता है जो स्वाभाविक रूप से उनके दिमाग की संज्ञानात्मक क्षमताओं को ख़राब करती है जो आपराधिक जिम्मेदारी से छूट का आधार बन सकती है। स्टीफ़न इन हिस्ट्री ऑफ़ द क्रिमिनल एनवी ऑफ़ इंग्लैंड, वॉल्यूम 11, पृ. 166 में देखा गया है कि कुछ लोगों ने एक सोते हुए आदमी का सिर काट दिया क्योंकि जब वह उठेगा तो उसे खोजते हुए देखना बहुत मजेदार होगा, जाहिर तौर पर यह एक आसानी होगी जहां कृत्य का अपराधी शारीरिक रूप से जानने में असमर्थ होगा उसके कृत्य का प्रभाव. कानून कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थता के अलावा कुछ भी नहीं मानता है और यह मानता है कि जहां किसी व्यक्ति का दिमाग या उसकी सामाजिक क्षमताएं यह समझने के लिए पर्याप्त रूप से कमजोर हैं कि वह क्या कर रहा है, उसे हमेशा अपने द्वारा किए गए कार्य के परिणाम का इरादा होना चाहिए। किसी अपराध के लिए केवल मकसद का अभाव, चाहे वह कितना भी क्रूर क्यों न हो, दलील और कानूनी पागलपन के सबूत के अभाव में, इस धारा में सहजता नहीं ला सकता, इस न्यायालय ने श्क्रैल वाली मोहम्मद बनाम महाराष्ट्र राज्य में माना कि: (एससीसी पृष्ठ 79)

"केवल यह तथ्य साबित नहीं हुआ है कि आरोपी ने अपनी पत्नी और ची आईडी की हत्या क्यों की या (कार्य यह है कि उसने दरवाजा खुलने पर भागने का कोई प्रयास नहीं किया) उसे तोड़ दिया गया था, इससे यह संकेत नहीं मिलेगा कि वह पागल था या उसके पास अपराध के लिए आवश्यक मेन्स रीया नहीं था।"

12. केवल मन की असामान्यता या आंशिक भ्रम, अप्रतिरोध्य आवेग या मनोरोगी का बाध्यकारी व्यवहार धारा 84 के तहत कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करता है क्योंकि उस धारा में निहित कानून अभी भी पूरी तरह से 19वीं सदी के इंग्लैंड के पुराने एम' नॉटन नियमों पर आधारित है। धारा 84 के प्रावधान वस्तुतः वही हैं जो एम' नॉटन की सहजता से, लॉर्ड्स की जूं द्वारा पूछे गए प्रश्नों के न्यायाधीशों के उत्तरों में निर्धारित किए गए हैं। घटना के समय आरोपी की मानसिक स्थिति का पता लगाने के लिए व्यवहार, पूर्ववृत्त, परिचारक और घटना के बाद के मामले प्रासंगिक हो सकते हैं, लेकिन समय में उतना दूर नहीं। अपराध करते समय या अपराध करने के तुरंत बाद अपराधी के मन की सटीक स्थिति को साबित करना मुश्किल है, लेकिन इसका कुछ संकेत अक्सर अपराध करते समय या अपराध करने के तुरंत बाद अपराधी के आचरण से मिलता है। एक पागल व्यक्ति का स्पष्ट अंतराल केवल विकार के हिंसक लक्षणों की समाप्ति नहीं है, बल्कि व्यक्ति को कार्य का निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त रूप से चंचल मन की क्षमताओं की बहाली है; लेकिन अभिव्यक्ति का मतलब जरूरी नहीं कि पूर्ण या सटीक बहाली हो मानसिक क्षमताएँ अपनी मूल स्थिति में। इसलिए, यदि ऐसी कोई बहाली होती है, तो संबंधित व्यक्ति ऐसे कारण, स्मृति और निर्णय के साथ कार्य कर सकता है कि यह एक कानूनी कार्य बन

जाए; लेकिन केवल विकार के हिंसक लक्षणों की समाप्ति है पर्याप्त नहीं है। ठीक है, या कि जिन शारीरिक और मानसिक बीमारियों से वह पीड़ित था, उसने उसकी बुद्धि को कमजोर कर दिया था और उसकी भावनाओं और इच्छाशक्ति को प्रभावित किया था, या कि उसने अतीत में कुछ असामान्य कार्य किए थे या वह बार-बार पागलपन के दौरों के शिकार होने के लिए उत्तरदायी था। छोटे-छोटे अंतराल, या यह कि उसे मिर्गी के दौरे आते थे, लेकिन उसके व्यवहार में कुछ भी असामान्य नहीं था, या यह कि उसका व्यवहार अजीब था, इस धारा के आवेदन को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। "

(v) इलावारासन बनाम राज्य[3] में (5), हत्या के आरोप के बचाव के रूप में विकृत दिमाग की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार चर्चा की: - (इस फैसले पर व्यापक रूप से चर्चा की जा रही है क्योंकि कुछ समानताएं इस हद तक खींची जा सकती हैं कि यह एक सहजता भी थी झगड़े के दौरान पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, जिसके बाद मानसिक विक्षिप्तता का बचाव किया गया।

x x x x x x

'"22. हालांकि, सवाल यह है कि क्या अपीलकर्ता भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के लाभ का हकदार था, जो यह प्रावधान करता है कि कोई भी कार्य अपराध नहीं है, जो उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जो ऐसा करने के समय, मन की अस्वस्थता, कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ है या जो यह जानने में असमर्थ है कि वह जो कर रहा है, वह या तो गलत है या कानून के विपरीत है। द्वारा स्थापित पागलपन की दलील के संबंध में रिकॉर्ड पर साक्ष्य पर विचार करने से पहले अपीलकर्ता, हम दो पहलुओं का उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं जो उन आसानियों के लिए प्रासंगिक हैं जहां किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति द्वारा बचाव में पागलपन की दलील दी जाती है। पहला पहलू उन परिस्थितियों के अस्तित्व को साबित करने के बोझ से संबंधित है जो आसानी लाएंगे आई पी.सी. की धारा 84 के दायरे में। यह स्पष्ट है कि किसी अपराध के घटित होने को साबित करने का भार हमेशा अभियोजन पक्ष पर होता है और यह कभी भी बदलता नहीं है।

23. समान रूप से अच्छी तरह से स्थापित यह प्रस्ताव है कि यदि इरादा एक आवश्यक घटक है अभियुक्त के विरुद्ध कथित अपराध के संबंध में अभियोजन पक्ष को उस घटक को भी स्थापित करना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर दूसरे पर हमला करता है और उसे चोट पहुंचाता है, तो इस्तेमाल किए गए हथियार और शरीर की बाल्टी जिस पर हमला किया गया है, उसके आधार पर, यह मान लेना उचित होगा कि आरोपी का इरादा इस तरह का कारण बनने का था। चोट जो उसने पहुंचाई। ऐसा कहने के बाद, अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों के प्रभाव को खत्म करने के लिए आरोपी द्वारा धारा 84 का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी यह साबित करके ऐसा कर सकता है कि वह कार्य की प्रकृति को जानने में या यह जानने में असमर्थ था कि वह जो कर रहा था वह या तो गलत था या कानून के विपरीत था। लेकिन जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि धारा 84 आई.पीसी के तहत उसकी सहजता लाने का बोझ क्या है? उस प्रावधान के लाभ का दावा

[3] (2011) 7 SCC 110

करने वाले व्यक्ति पर पूरी तरह से निर्भर करता है।

24. साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 इस संबंध में प्रासंगिक है और इसे निकाला जा सकता है:

"105. यह साबित करने का भार कि अभियुक्त की सहजता अपवादों के अंतर्गत आती है। जब किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगाया जाता है, तो भारतीय दंड संहिता, (1860 का 45) में किसी भी सामान्य अपवाद के अंतर्गत सहजता लाने वाली परिस्थितियों के अस्तित्व को साबित करने का भार या उसी संहिता के किसी अन्य भाग में या अपराध को परिभाषित करने वाले किसी भी कानून में निहित किसी विशेष अपवाद या प्रावधान के भीतर, उस पर है, और न्यायालय ऐसी परिस्थितियों की अनुपस्थिति का अनुमान लगाएगा। "

25. उपरोक्त का सावधानीपूर्वक अध्ययन यह दिखाएगा कि न केवल अभियुक्त पर एक अपवाद साबित करने का बोझ है, बल्कि अदालत उन परिस्थितियों की अनुपस्थिति को भी मान लेगी जो भारतीय दंड संहिता में किसी भी सामान्य अपवाद के भीतर या किसी विशेष अपवाद या प्रावधान के भीतर उसकी आसानी ला सकती है। दह्याभाई छगनभाई ठक्कर बनाम स्टेट ऑफ गुजरात में इस न्यायालय के निर्णय के बाद उक्त संहिता या अपराध को परिभाषित करने वाले कानून की कोई भी पंक्ति सबूत के बोझ को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की समय पर याद दिलाने के रूप में काम कर सकती है, जहां आरोपी आसानी से एक अपवाद का अनुरोध करता है: (एआईआर पी. 1568, पैरा 7)

"7. 'पागलपन की दलील के संदर्भ में सबूत के बोझ के सिद्धांत को निम्नलिखित प्रस्तावों में कहा जा सकता है:

(I) अभियोजन पक्ष को उचित संदेह से परे साबित करना होगा कि आरोपी ने अपेक्षित आपराधिक दंड के साथ अपराध किया था, और का बोझ यह साबित करना कि मुकदमे की शुरुआत से अंत तक हमेशा अभियोजन पक्ष पर निर्भर रहता है।

(2) एक खण्डन योग्य धारणा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 84 द्वारा निर्धारित अर्थों में, जब अभियुक्त ने अपराध किया था, तब वह पागल नहीं था: अभियुक्त अदालत के समक्ष सभी प्रासंगिक मौखिक साक्ष्य रखकर इसका खण्डन कर सकता है। दस्तावेजी या परिस्थितिजन्य, लेकिन उस पर सबूत का बोझ सिविल कार्यवाही के एक पक्ष से अधिक नहीं है।

(3) यदि अभियुक्त निर्णायक रूप से यह स्थापित करने में सक्षम नहीं था कि जब उसने अपराध किया तो वह पागल था अपराध किया है, तो अभियुक्त या अभियोजन पक्ष द्वारा अदालत के समक्ष रखे गए साक्ष्य से अदालत के मन में अपराध के एक या अधिक अवयवों के संबंध में उचित संदेह पैदा हो सकता है, जिसमें अभियुक्त का पुरुष अपराध भी शामिल है। आसानी से अदालत आरोपी को इस आधार पर बरी करने की हकदार होगी कि अभियोजन पक्ष पर पड़े सबूत के सामान्य बोझ से मुक्ति नहीं मिली है। धारा 105 (सुप्रा) के तहत उस पर डाले गए बोझ के निर्वहन के लिए संतुष्ट होना होगा, जैसा कि अभियोजन से अपेक्षित नहीं है।

26. दूसरा पहलू जिसका हमें उल्लेख करने की आवश्यकता है वह यह है कि धारा 105 (सुप्रा) के तहत उस पर डाले गए बोझ से मुक्ति के लिए अभियुक्त को सबूत का जो मानक पूरा करना होता है वह वैसा नहीं है जैसा कि अभियोजन से अपेक्षित है। इस न्यायालय के निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला ने इस विषय पर कानूनी प्रस्ताव को आधिकारिक रूप से तय कर दिया है। इस संबंध में संदर्भ यूपी राज्य बनाम राम स्वैम्प में इस मामले के फैसले के लिए, यह पर्याप्त होना चाहिए जहां इस अदालत ने कहा: (एससीसी पृष्ठ 774, पैरा 19)

“19. अपवाद को साबित करने का जो बोझ आरोपी पर है वह समान नहीं है उचित संदेह से परे आरोप साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष के बोझ के रूप में कठोरता। नागरिक सहजता की तरह, अभियुक्त के लिए यह दिखाना पर्याप्त है कि संभावनाओं की प्रधानता (उसके) पक्ष में है..." भिखारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में इस न्यायालय का निर्णय भी इसी आधार पर है।

27.आइए अब हम यह पता लगाने के लिए उपरोक्त प्रस्तावों के आलोक में रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर विचार करें कि क्या अपीलकर्ता ने I पीसी की धारा 84 के तहत अपनी सहजता लाने के बोझ का निर्वहन किया था। अपीलकर्ता ने कानूनी पागलपन की दलील का समर्थन करने के लिए बचाव में कोई सबूत नहीं दिया है। 1 टोपी एक महत्वपूर्ण पहलू हो सकता है लेकिन किसी भी तरह से स्पष्ट उपयोग नहीं है। क्योंकि किसी अभियुक्त के लिए यह खुला है कि वह अपवाद के लाभ का दावा करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री पर भरोसा कर सके। 1 बचाव में साक्ष्य आसानी से अधिशेष हो सकता है जहां अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर बचाव पक्ष आरोपी को बरी करने में आसानी कर सकता है।

28.उपरोक्त के आलोक में विचार करने योग्य बात यह है कि क्या वर्तमान मौजूद है ऐसी ही एक आसानी है जहां पागलपन का मामला - अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए सबूतों और मुकदमे में जांचे गए अदालती गवाहों द्वारा साबित या संभावित है। अभियोजन पक्ष के दो गवाहों की गवाही पीडब्लू2, धनलक्ष्मी और पीडब्लू3, वल्ली तुरंत महत्व मान लेता है जिसका हम इस स्तर पर उल्लेख कर सकते हैं।

(न्यायधीश अमोल रतन सिंह)

धनलक्ष्मी ने मृत्यु की ओर ले जाने वाली घटनाओं का अनुक्रम बताने के अलावा, कहा है कि उनके पति एक सरकारी कर्मचारी हैं, जिन्हें 4000/- रुपये का मासिक वेतन मिलता है। घरेलू खर्चों को पूरा करने के लिए गवाह को सौंप देंगे। उन्होंने आगे कहा कि दंपति ने पांच साल तक शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन बिताया, लेकिन अपीलकर्ता और उसके मामा कन्नन के बीच संपत्ति को लेकर विवाद था, जिसमें से एक बाल्टी अपीलकर्ता पहले ही बेच चुका था और शेष वह बेचना चाहता था। . 'गवाह के अनुसार, अपीलकर्ता ने दोपहर 12 बजे के आसपास झगड़ा शुरू किया था। लेकिन एक घंटे बाद उसके साथ मारपीट की। गवाह ने आगे कहा कि अपीलकर्ता कुछ दवाएं लेती थी, लेकिन उसे क्लिनिक का नाम याद नहीं था, जहां इलाज किया जा रहा था। गवाह के अनुसार, अपीलकर्ता का इलाज कर रहे मनोचिकित्सक ने उसकी चिकित्सीय स्थिति को अत्यधिक शराब पीने का परिणाम बताया था और

सलाह दी थी कि यदि अपीलकर्ता नियमित रूप से दवाएँ लेगा तो वह ठीक हो जाएगा।

29.यह हमें पीडब्लू3, श्रीमती वल्ली, अपीलकर्ता की मां के बयान पर लाता है। गवाह ने जिरह में कहा है कि अपीलकर्ता पीडब्ल्यूडी बंगले में चौकीदार के रूप में काम करता था और वह अपीलकर्ता के कार्यालय में उसका दोपहर का भोजन पहुंचाती थी। उन्होंने पारिवारिक संपत्तियों को लेकर अपीलकर्ता और उसके चाचा के बीच विवाद का भी जिक्र किया, जिसके संबंध में उन्होंने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। घटना वाले दिन, परिवार ने रात करीब 9 बजे खाना खाया और बिस्तर पर चला गया। लेकिन दोपहर करीब एक बजे दंपति में झगड़ा होने लगा। जिससे पीडब्लू2, धनलक्ष्मी पर हमला हुआ। गवाह ने कहा कि अपीलकर्ता का पीक्रुमल कोवी स्ट्रीट पर स्थित एक क्लिनिक में मनोचिकित्सक से इलाज चल रहा था और डॉक्टर ने अपीलकर्ता को मानसिक विकार बताया था जिसके कारण वह अक्सर क्रोधित हो जाता था।

30. उपरोक्त दो गवाहों के बयान, जो अपीलकर्ता के करीबी परिवार के सदस्य हैं, यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि अपीलकर्ता घटना के समय या उससे पहले किसी भी समय मानसिक रूप से अस्वस्थ था। तथ्य यह है कि अपीलकर्ता एक सरकारी कर्मचारी के रूप में काम कर रहा था और एक चौकीदार के रूप में तैनात था और उसके कर्तव्यों की देखरेख करने वाले किसी भी व्यक्ति से उसके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कोई शिकायत नहीं थी, यह महत्वपूर्ण है। यह तथ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि उनकी पत्नी श्रीमती धनलक्षिम, जो उनके साथ एक ही छत के नीचे रह रहा था, ने भी अपीलकर्ता को नींद न आने जैसी कोई बीमारी नहीं बताई, जिसे डॉक्टर ने अत्यधिक शराब पीने का परिणाम बताया था। पीडब्लू 3, वल्ली का बयान कि उसका बेटा मानसिक विकार का इलाज करा रहा था, इस अदालत के लिए मानसिक रूप से अस्वस्थता के निष्कर्ष को दर्ज करने के लिए बहुत अस्पष्ट और अपर्याप्त है, खासकर जब गवाह कई चोटों के बावजूद मुकदमे में मुकर गया था। उसने इसे अपने घर के अंदर गिरने का कारण बताने की कोशिश की। 'मेरे गवाह का यह बयान कि उसका बेटा किसी मानसिक विकार का इलाज करा रहा था, इन परिस्थितियों में अंकित मूल्य पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है, उसके आधार पर अपीलकर्ता के पक्ष में बरी करने का आदेश दिया जा सकता है। यह स्पष्ट है कि मां ने पाला बदल लिया है। उसके बेटे को उसके आपराधिक कृत्य से उत्पन्न होने वाली भावनाओं से बचाएं।

31. मनोरोग विशेषज्ञ डॉ. बी. श्रीनिवासन ने अपने बयान में कहा कि अपीलकर्ता को रियाल कोर्ट द्वारा पारित एक आदेश के अनुसार 29 जुलाई, 2002 को कराईकल के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसमें उसकी मेडिकल जांच का निर्देश दिया गया था ताकि उसका मूल्यांकन किया जा सके। मानसिक स्थिति और बातचीत करने की क्षमता। इली गवाह ने आगे कहा कि अपीलकर्ता को 29 जुलाई 2000 की दोपहर से 6 अगस्त 2002 तक निगरानी में रखा गया था, इस दौरान उसने पाया कि वह सचेत था, पर्याप्त रूप से कपड़े पहने हुए था और बातचीत करने में सक्षम था।

32. डॉक्टर ने इस अवधि के दौरान अपीलकर्ता की स्थिति का वर्णन निम्नलिखित शब्दों में किया है:

"उसे बेचैनी है, समय-समय पर इधर-उधर देखने पर संदेह होता है, अनुचित मुस्कुराहट होती है, कुछ आंतरिक आवाज उसे बताने की शिकायत करती है (कभी-कभी स्वभाव से अपमानजनक), अपने बारे में दूसरों की राय को लेकर डर और चिंता है, जेल अकेले रहना चाहता है, कहता है कि उसे रात में शांति से सोने के लिए शराब के कुछ पैग चाहिए। उसे कभी-कभी अपने भीतर की फुसफुसाहट के बारे में भ्रम होता है, उसे अपनी छाती और मस्तिष्क के बीच कुछ खिंचाव महसूस होता है, जो उसे लोगों के साथ और परीक्षक के साथ खुलकर बात करने से रोकता है। मेरा मानना है कि उपरोक्त व्यक्ति विकृत दिमाग का है। संभावित चिकित्सा वितरण मनोविकृति है। इस मामले में विभेदक निदान पर विचार किया गया है:

1.पैरानॉयड साइकोसिस (सिज़ोफ्रेनिया)

2.पदार्थ प्रेरित साइकोसिस (शराब प्रेरित)

3.ऑर्गेनिक साइकोसिस/ऑर्गेनिक मानसिक विकार

(मैं चोट अनुक्रम का नेतृत्व करता हूं, व्यक्तित्व परिवर्तन)

इसलिए मैं इस माननीय न्यायालय से अनुरोध करता हूं कि कृपया इस मामले में किसी अन्य सलाहकार मनोचिकित्सक द्वारा दूसरी राय और एक नैदानिक मनोवैज्ञानिक द्वारा मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन की भी व्यवस्था की जाए। (जोर दिया गया)

33. अपीलकर्ता को डॉ. बी. श्रीनिवासन द्वारा की गई सिफारिशों के आलोक में, पांडिचेरी के जेआईपीएम एआर अस्पताल में भेजा गया, जहां वह डॉ. आर. चन्द्रशेखर, सीडब्ल्यू2 की देखरेख में रहे, जो वहां मौजूद थे। उस अस्पताल में मनोचिकित्सा विभाग के प्रोफेसर और प्रमुख। अदालत के समक्ष अपने बयान में डॉ. चन्द्रशेखर ने कहा कि अपीलकर्ता को 30 सितंबर, 2002 को भर्ती कराया गया था, लेकिन 1 अक्टूबर, 2002 को वह अस्पताल से भाग गया, जिसके संबंध में डॉक्टर ने एक्जीबिट .Pl अंकित रिपोर्ट बनाई। प्रासंगिक रिकॉर्ड की जांच करने के बाद गवाह ने बताया कि अपीलकर्ता में साइकैटैक्सिया के कोई लक्षण नहीं थे। गवाह द्वारा साबित की गई विस्तृत रिपोर्ट और Ex.P2 में अपीलकर्ता की चिकित्सीय स्थिति का वर्णन इस प्रकार किया गया है:

"उसे अच्छी तरह से तैयार किया गया था। तालमेल स्थापित किया गया. कोई असामान्य मोटर संबंधी व्यवहार मौजूद नहीं था। 1 यानी सहयोगी था. 11 को मनोदशा उदासीन दिखाई दी और वाणी सामान्य थी। औपचारिक विचार विकार या कब्जे या विचार सामग्री के विकार का कोई सबूत नहीं था। कोई भी अवधारणात्मक विकार स्पष्ट नहीं था। ध्यान उत्तेजित था और एकाग्रता अच्छी तरह कायम थी। वह समय, स्थान, व्यक्ति के प्रति उन्मुख थे। यानी तत्काल स्मरण, हालिया और दूरस्थ स्मृति बरकरार थी। अमूर्तन कार्यात्मक स्तर पर था। फैसला सुरक्षित रखा गया, अंतर्दृष्टि मौजूद थी।"

34. अंतिम रिपोर्ट में डॉक्टर ने अपीलकर्ता के मानसिक स्वास्थ्य और मनो-नैदानिक मूल्यांकन के बारे में

निम्नलिखित कलम चित्र खींचा है।

"मनो-नैदानिक मूल्यांकन:

रोगी की धारणा, स्मृति और बुद्धि थोड़ी कम थी क्षीण (मेमोरी कोशेंट 70 था और पीसीआर फ़ोमेंस कोशेंट 72 था)। मुख्य रूप से एएफटीसीटीवीसी गड़बड़ी के साथ मिश्रित मनोवैज्ञानिक तस्वीर सामने आई थी। यानी व्यावसायिक क्षेत्र में अतिरिक्त समर्थन और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मरीज़ का विटामिन और क्लोरप्रोमेज़िन 100mg से इलाज चल रहा था। वार्ड में रहने के दौरान प्रति दिन। इस तथ्य को छोड़कर कि 1.10.2002 को एचसीकैब वार्ड से भाग गई थी, अस्पताल में पाठ्यक्रम सामान्य नहीं था। मेरी राय है कि उपरोक्त व्यक्ति वर्तमान में किसी भी मानसिक लक्षण से पीड़ित नहीं है, जो उसकी रक्षा करने की क्षमता में हस्तक्षेप कर सकता है।

एसडी/-

(डॉ. आर. चंद्राशकरण)

मनोचिकित्सा विभाग के प्रमुख

जिपमेर,

डीटी. 5-10-2002 पांडिचक्राई-6"

35. महत्वपूर्ण बात यह है कि मुकदमे के दौरान अदालत के गवाह के रूप में जिन दो डॉक्टरों की गवाही की जांच की गई, वे डॉक्टरों द्वारा जांच के समय अपीलकर्ता की मानसिक स्वास्थ्य स्थिति से संबंधित हैं, न कि अपराध के घटित होने से, जो कि प्रासंगिक बिंदु है। धारा 84 I. पीसी के लाभ का दावा करने के लिए रिकॉर्ड पर उपलब्ध फ़्लिक मेडिकल राय केवल इस सवाल से संबंधित है कि क्या अपीलकर्ता किसी मानसिक या अन्य बीमारी से पीड़ित है जो उसे मुकदमे में अपना बचाव करने से रोक सकती है। यह सच है कि यह निर्धारित करते समय कि क्या अभियुक्त धारा 84 आई.पी.सी. के लाभ का हकदार है। न्यायालय को उन परिस्थितियों पर विचार करना होगा जिनके कारण अपराध हुआ, उसमें भाग लिया गया या उसके बाद अपराध हुआ, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि ऐसी परिस्थितियों को विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए। इस आसानी से कोई ऐसा सबूत नहीं दिया गया है। इसके विपरीत, जिपमर के डॉ. चन्द्रशेखर के बयान और प्रमाणपत्रों से युक्त विशेषज्ञ साक्ष्य स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि कैपलेंट किसी भी चिकित्सीय लक्षण से पीड़ित नहीं था जो उसकी रक्षा करने की क्षमता में हस्तक्षेप कर सकता था।

36. 'किसी भी मानसिक विक्षिप्तता का सुझाव देने वाला कोई सबूत नहीं है अपीलकर्ता ने अपराध के समय न तो पत्नी और न ही यहां तक कि उसकी मां ने भी कई शब्दों में यह सुझाव दिया कि मानसिक कमजोरी तो छोड़ ही दें, जो उसे अपने कार्यों की प्रकृति और परिणामों को समझने से रोकती है। 'जिस डॉक्टर पर आरोप है

कि उसने अनिद्रा का इलाज किया था, उसकी भी जांच नहीं की गई है और न ही उसके मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति से परिचित किसी ने भी पागलपन की दलील का समर्थन करने के लिए गवाह बॉक्स में कदम रखा है, 'यहां यह कहने का कोई मतलब नहीं है कि पागलपन है यह एक चिकित्सीय स्थिति है जिसे संबंधित व्यक्ति के दोस्तों और रिश्तेदारों से लंबे समय तक छुपाया नहीं जा सकता है। उस दृष्टि से अपीलकर्ता की ओर से किसी भी अतार्किक या विलक्षण व्यवहार को देखने वाले किसी भी व्यक्ति का प्रस्तुत न होना उल्लेखनीय है। यह कहना पर्याप्त है कि अपीलकर्ता द्वारा की गई पागलपन की दलील न तो प्रमाणित थी और न ही संभावित थी।

(28) यहां वर्तमान सहजता में यह उल्लेख करना उचित होगा कि, पीजीआईएमएस, रोहतक के विशेषज्ञ चिकित्सा राय से पहले, चिकित्सा अधिकारी, जिला जेल, नारनौल ने जेल अधीक्षक को इस आशय का पत्र लिखा था। अपीलकर्ता सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है, हालांकि अंततः इसका निदान "लगातार भ्रम संबंधी विकार जैसी स्थिति" के रूप में किया गया। सिज़ोफ्रेनिया की बीमारी के संबंध में, सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित निर्णयों को सफलतापूर्वक दोहराया जा सकता है, जिसमें धारा 84 आई पीसी के तहत बचाव की याचिका फिर से खारिज कर दी गई थी:

(i) सुधाकरन बनाम केरल राज्य[4] (6), जिसमें यह देखा गया है:

“9. इसके बाद एफएचसी ट्रायल कोर्ट ने धारा 84 I पीसी के तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर बचाव पर विचार किया। संपूर्ण चिकित्सा साक्ष्य की जांच करने पर, ट्रायल कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि यह इंगित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि अपराध के समय या घटना के घटित होने से ठीक पहले, अपीलकर्ता किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित था। हालाँकि उन्होंने मानसिक बीमारी के लिए साल 1985 में कुछ इलाज करवाया था लेकिन वह उससे पूरी तरह ठीक हो गए थे। इसके बाद, उसके काफी समय बाद उन्होंने मृतक से शादी कर ली। भले ही वे अशांत वैवाहिक जीवन जी रहे थे, विवाह के बाद एक बच्चे का जन्म हुआ, 'जिस समय अपराध किया गया था उस समय बच्चा 8 महीने का था। 'ट्रायल कोर्ट ने यह भी देखा कि, हालांकि अपीलकर्ता अनियमित था, वह अपनी जीविका के लिए आकस्मिक नौकरियां करता था। ट्रायल कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर ध्यान देने के बाद भी, निष्कर्ष यह था कि अपीलकर्ता अधिनियम की प्रकृति और उसके परिणामों को समझने में सक्षम था।

10.से 15 x x x x x

16. जैसा जहां तक, धारा 84 के तहत बचाव का सवाल है, हमें ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई राय से असहमत होने का कोई कारण नहीं दिखता है। इद्दुकी जिला अस्पताल के सहायक सर्जन डीडब्ल्यू1 द्वारा दिए गए साक्ष्य को प्रथम उच्च न्यायालय ने सही ढंग से खारिज कर दिया है। यह सच है कि DW1 ने स्काउट रोगी रजिस्टर के आधार पर कहा था कि अपीलकर्ता परामर्श के लिए आया था। मुझे पता है, उसे क्या उपचार दिया गया था, इसका कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। जीवित बाह्य रोगी का टिकट नहीं बनाया गया।

[4] AIR 2011 (SC) 265

आख़िरकार, इस डॉक्टर ने स्वीकार किया कि वह यह नहीं कह सकता कि अपीलकर्ता वहाँ मनोरोग उपचार के लिए आया था। मुझे वह दवा भी याद नहीं है जो अपीलकर्ता को दी गई थी। इसी प्रकार, जेल अधीक्षक डीडब्ल्यू2 के साक्ष्य भी केवल यह इंगित करते हैं कि अपीलकर्ता को मेडिकल स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया था। स्वास्थ्य केंद्र की सीवीआईडीएनसी अधूरी और पूरी तरह से अविश्वसनीय थी, क्योंकि पेश किए गए सभी मेडिकल साक्ष्य यह दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं थे कि हत्या के समय अपीलकर्ता चिकित्सकीय रूप से पागल था और उसके परिणामों की प्रकृति को समझने में असमर्थ था की उसके द्वारा किया गया कार्य।

17. पहले के समय में, इसे आमतौर पर क्षमा मांगने के औचित्य के रूप में आगे बढ़ाया जाता था। समय के साथ, इसका उपयोग मेन्स रीया से जुड़े अपराधों में आपराधिक दायित्व के पूर्ण बचाव के रूप में किया जाने लगा। यह भी स्वीकार किया जाता है कि चिकित्सीय दृष्टि से पागलपन कानूनी पागलपन से भिन्न है। भारत में ज्यादातर मामलों में पागलपन के बचाव की वकालत की जाती है, जहां अपराधी को सिज़ोफ्रेनिया की बीमारी से पीड़ित बताया जाता है। 'वर्तमान मामले में दलील यह भी थी कि अपीलकर्ता "पैरानॉयड सिज़ोफ्रेनिया" से पीड़ित था। इस शब्द को मोदी के मेडिकल न्यायशास्त्र और 'टॉक्सिकोलॉजी' में इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

“व्यामोह को अब व्यामोह सिज़ोफ्रेनिया का एक हल्का रूप माना जाता है। यह महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक होता है। 'इस बीमारी की मुख्य विशेषता व्यक्तित्व में एक जटिल भ्रमपूर्ण प्रणाली है जो अन्यथा अच्छी तरह से संरक्षित है। '1'एचसी भ्रम उत्पीड़क प्रकार का होता है। 'यानि इस बीमारी की वास्तविक प्रकृति को लंबे समय तक पहचाना नहीं जा सकता है क्योंकि व्यक्तित्व अच्छी तरह से संरक्षित है, और इनमें से कुछ पागल लोग समाज सुधारकों या अजीब छद्म-धार्मिक संप्रदायों के संस्थापकों के रूप में सामने आ सकते हैं। 'हाय शास्त्रीय चित्र दुर्लभ है और आम तौर पर एक दीर्घकालिक पाठ्यक्रम लेता है।

अधिकांश मामलों में पैरानॉयड सिज़ोफ्रेनिया, चौथे दशक में शुरू होता है और घातक रूप से विकसित होता है। संदेह प्रारंभिक अवस्था का विशिष्ट लक्षण है। संदर्भ के विचार उत्पन्न होते हैं, जो धीरे-धीरे उत्पीड़न के भ्रम में विकसित होते हैं। इसके बाद श्रवण मतिभ्रम होता है, जो शुरुआत में कानों में आवाज या शोर के रूप में शुरू होता है, लेकिन बाद में गाली-गलौज या अपमान में बदल जाता है। भ्रम पहले अनिश्चित होते हैं, लेकिन धीरे-धीरे वे स्थिर और निश्चित हो जाते हैं, जिससे रोगी को यह विश्वास हो जाता है कि उसे किसी अज्ञात व्यक्ति या किसी अलौकिक एजेंसी द्वारा सताया जा रहा है। मेरा मानना है कि उसके भोजन में जहर मिलाया जा रहा है, कुछ हानिकारक गैसें उसके कमरे में प्रवाहित हो रही हैं और लोग उसे बर्बाद करने की साजिश रच रहे हैं। सामान्य संवेदना की गड़बड़ी मतिभ्रम को जन्म देती है जो सम्मोहन, बिजली, वायरलेस टेलीग्राफी या परमाणु एजेंसियों के प्रभाव के कारण होती है। इन दर्दनाक और अप्रिय मतिभ्रमों और भ्रमों के कारण रोगी बहुत चिड़चिड़ा और उत्तेजित हो जाता है। ”

मैं चिकित्सा पेशे से निस्संदेह यहां अपीलकर्ता को मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के रूप में मानूंगा। हालाँकि, कानून में पागलपन के बचाव के लाभ का दावा करने के प्रयोजनों के लिए, अपीलकर्ता को यह साबित करना

होगा कि जिस समय अपराध किया गया था, उस समय उसकी संज्ञानात्मक क्षमताएँ इतनी क्षीण थीं कि उसे कृत्य की प्रकृति का पता ही नहीं चल पाया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 84 पागलपन की रक्षा को मान्यता देती है। इसे इस प्रकार परिभाषित किया गया है:- (जोर दिया गया)

"कोई भी कार्य ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध नहीं है जो ऐसा करते समय मानसिक अस्वस्थता के कारण यह जानने में असमर्थ हो कि कार्य की प्रकृति क्या है, या वह क्या कर रहा है क्या गलत है या कानून के विपरीत है।" उसके द्वारा। वैकल्पिक मामले में, उसे यह साबित करना होगा कि वह यह जानने में असमर्थ है कि वह जो कर रहा है वह या तो गलत है या कानून के विपरीत है। उपरोक्त अनुभाग स्पष्ट रूप से पागलपन की रक्षा को वैधानिक मान्यता देता है जैसा कि आर.वी बनाम डेनियल[5] उस मामले में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने पांच प्रश्नों के आधार पर प्रसिद्ध मैक नॉटेन नियम तैयार किए, जो उन्हें पागलपन की रक्षा के संबंध में संदर्भित किए गए थे।

(29) किसी अभियुक्त के अपराध के निर्धारण के प्रश्न के संदर्भ में भ्रम से कैसे निपटा जाए, इस मुद्दे पर, सुप्रीम कोर्ट ने आर. डेनियल मी नॉटसीएन, 1843 आरआर 59: 8 ईआर 718 (एचएल)। सुधाकरन के मामले (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को फिर से उद्धृत करते हुए, निम्नलिखित अंश दिए गए हैं:-

17. x x x x x

"यह संदर्भ एक ऐसे मामले में दिया गया था जहां मैकनॉटन पर एडवर्ड ड्रमंड, जो प्राइवेट था, की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया गया था। इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधान मंत्री सर रॉबर्ट पील के सचिव। आरोपी मैकनॉटन ने यह साबित करने के लिए चिकित्सीय साक्ष्य प्रस्तुत किए कि, कृत्य करते समय उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। 1 यानी दावा किया कि वह एक पागल भ्रम से पीड़ित थे कि उनकी सभी समस्याओं का एकमात्र कारण प्रधान मंत्री थे। उन्होंने यह भी दावा किया था कि पागल भ्रम के परिणामस्वरूप, उन्होंने ड्रमंड को प्रधान मंत्री समझ लिया और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। पागलपन की दलील स्वीकार कर ली गई और मुझे नॉटन को पागलपन के आधार पर दोषी नहीं पाया गया। यानी उपरोक्त फैसला हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बहस का विषय बन गया। इसलिए, ऐसी सहजताओं को नियंत्रित करने वाले कानून पर सभी न्यायाधीशों की राय लेने का निर्णय लिया गया। बाद में लॉ लॉर्ड्स से पांच प्रश्न पूछे गए। लॉर्ड चीफ जस्टिस टिंडल द्वारा दिए गए प्रश्न और उत्तर इस प्रकार थे:-

"प्र. 1 क्या एक या अधिक विशिष्ट विषयों या व्यक्तियों के संबंध में पागल भ्रम से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किए गए कथित अपराधों का सम्मान करने वाला कानून है: उदाहरण के लिए, जहां कथित अपराध के समय आरोपी को पता था कि वह इसके विपरीत कार्य कर रहा है एलबीडब्ल्यू, लेकिन क्या इस कृत्य की शिकायत पागल भ्रम के प्रभाव के तहत, किसी कथित शिकायत या चोट का बदला लेने के लिए, या कुछ सार्वजनिक लाभ उत्पन्न करने के उद्देश्य से की गई थी?

---

[5] 1843 आरआर 59: 8 ईआर 718 (एचएल)

उत्तर

"यह मानते हुए कि आपके आधिपत्य की पूछताछ सीमित है उन व्यक्तियों के लिए जो केवल इस तरह के आंशिक भ्रम के तहत काम करते हैं, और अन्य मामलों में पागल नहीं हैं, हमारी राय है कि, जिस पक्ष ने शिकायत की थी उसके बावजूद, पागल भ्रम के प्रभाव के तहत, कुछ का निवारण करने या बदला लेने के उद्देश्य से कार्य किया था कथित शिकायत या चोट, या कुछ सार्वजनिक लाभ उत्पन्न करने के बावजूद, वह अपराध की प्रकृति के अनुसार दंडनीय है, यदि वह जानता था, ऐसा अपराध करते समय, कि वह कानून के विपरीत कार्य कर रहा था, इस अभिव्यक्ति से हम अपने आधिपत्य का मतलब देश का कानून समझें।

प्र.2. जब किसी व्यक्ति पर एक या अधिक विशिष्ट विषयों या व्यक्तियों के संबंध में पागल भ्रम से पीड़ित होने का आरोप लगाया जाता है, उस पर अपराध (उदाहरण के लिए हत्या) करने का आरोप लगाया जाता है, और पागलपन स्थापित किया जाता है, तो जूरी को प्रस्तुत किए जाने वाले उचित प्रश्न क्या हैं? बचाव के रूप में?

प्र.3. किस संदर्भ में यह प्रश्न जूरी पर छोड़ा जाना चाहिए कि उस समय कैदी की मानसिक स्थिति क्या थी जब कृत्य किया गया था?

उत्तर - दूसरे और तीसरे प्रश्न के लिए

'यह कि जूरी को सभी मामलों में बताया जाना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति यह माना जाता है कि वह समझदार है और उसके पास अपने अपराधों के लिए जिम्मेदार होने के लिए पर्याप्त कारण हैं, जब तक कि उनकी संतुष्टि के लिए इसके विपरीत साबित न हो जाए; और यह कि, पागलपन के आधार पर बचाव स्थापित करने के लिए, यह स्पष्ट रूप से साबित किया जाना चाहिए कि, कार्य करने के समय, आरोपी पक्ष देशद्रोह के ऐसे दोष के तहत काम कर रहा था, दिमाग की बीमारी से, जैसे कि उसे पता ही नहीं था वह जो कार्य कर रहा था उसकी प्रकृति और गुणवत्ता, या यदि उसे यह पता था, कि वह नहीं जानता था कि वह जो कर रहा था वह गलत था। इन अवसरों पर प्रश्न के उत्तरार्ध को जूरी के सामने रखने का तरीका आम तौर पर यह रहा है कि क्या आरोपी को कार्य करते समय सही और गलत के बीच का अंतर पता था, कौन सा तरीका, हालांकि शायद ही कभी, अग्रणी हो जूरी के साथ कोई भी गलती, जैसा कि हम कल्पना करते हैं, आम तौर पर और अमूर्त रूप में इतनी सटीक नहीं होती है, जितनी कि पार्टी के सही और गलत के ज्ञान के संबंध में होती है।

प्र.4. यदि कोई व्यक्ति मौजूदा तथ्यों के बारे में पागलपन के भ्रम में है और उसके परिणामस्वरूप अपराध करता है, तो क्या उसे माफ कर दिया गया है?

उत्तर-

'उत्तर, निश्चित रूप से, भ्रम की प्रकृति पर निर्भर होना चाहिए, लेकिन वही धारणा बनाना जैसा हमने पहले किया था, कि केवल इस तरह के आंशिक भ्रम के तहत काम किया जा सकता है, और अन्य मामलों में पागल नहीं है,

हमें लगता है कि वह जिम्मेदारी के रूप में उसी स्थिति में विचार किया जाना चाहिए जैसे कि जिन तथ्यों के संबंध में भ्रम मौजूद है वे वास्तविक थे। उदाहरण के लिए, यदि, अपने भ्रम के प्रभाव में, वह मानता है कि कोई अन्य व्यक्ति उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा है, और वह उस व्यक्ति को मार देता है, जैसा कि वह आत्मरक्षा में मानता है, तो उसे सजा से छूट दी जाएगी। यदि उसका भ्रम यह था कि मृतक ने उसके चरित्र और भाग्य को गंभीर चोट पहुंचाई है, और उसने ऐसी कथित चोट का बदला लेने के लिए उसे मार डाला, तो वह दंड का भागी होगा।

प्र.5. क्या पागलपन की बीमारी से परिचित एक चिकित्सक से, जिसने मुकदमे से पहले कैदी को कभी नहीं देखा था, लेकिन जो पूरे मुकदमे के दौरान और सभी गवाहों की जांच के दौरान उपस्थित था, उस समय कैदी के मन की स्थिति के बारे में उसकी राय पूछी जा सकती है। कथित अपराध के कमीशन के बारे में, या उसकी राय क्या कैदी को कृत्य करते समय यह पता था कि वह कानून के विपरीत काम कर रहा है, या क्या वह उस समय किसी और किस भ्रम के तहत काम कर रहा था?

उत्तर-

हमें लगता है कि कथित परिस्थितियों में, चिकित्सा आदमी से ऊपर बताए गए आधार पर सख्ती से उसकी राय नहीं पूछी जा सकती है, क्योंकि उनमें से प्रत्येक प्रश्न में तथ्यों की सच्चाई का स्पष्टीकरण शामिल है, जिसे तय करना जूरी का काम है; और ये प्रश्न केवल विज्ञान के विषय पर प्रश्न नहीं हैं, जिसमें आसानी से ऐसे साक्ष्य स्वीकार्य हैं। लेकिन जहां तथ्यों को स्वीकार किया जाता है या विवादित नहीं किया जाता है, और प्रश्न मूलतः केवल विज्ञान से संबंधित हो जाता है, तो प्रश्न को उस सामान्य रूप में रखने की अनुमति देना सुविधाजनक हो सकता है, हालांकि उस पर अधिकार के रूप में जोर नहीं दिया जा सकता है।

एक तुलना प्रश्न संख्या के उत्तर के 2 और 3 और आईपीसी की धारा 84 में निहित प्रावधान स्पष्ट रूप से इंगित करेगा कि धारा उक्त उत्तरों पर आधारित है।

(30) आगे, रतन लाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य[6] (8) में सर्वोच्च न्यायालय के पहले के फैसले का हवाला देते हुए, सुधाकरन (सुप्रा) में निम्नलिखित अंश उद्धृत किए गए थे:

19.x x x x x x

अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि समय का महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर मन की अस्वस्थता स्थापित की जानी चाहिए वह वह समय है जब अपराध वास्तव में किया गया है और इसे साबित करने का भार अपीलकर्ता पर है।

निष्कर्ष में, यह कहा गया था सुधाकरन का मामला (सुप्रा):

---

[6] (1970)7 SCC 533

“21. उच्च न्यायालय ने परिस्थितियों की समग्रता पर विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह दर्शाता हो कि अपीलकर्ता महत्वपूर्ण समय में मानसिक बीमारी से पीड़ित था। रिकॉर्ड पर रखे गए केवल साक्ष्य से पता चलता है कि अपीलकर्ता का वर्ष 1985 में 13 दिनों के लिए एक मनोरोग अस्पताल में इलाज किया गया था, उस समय भी डॉक्टर ने बीमारी को मनोवैज्ञानिक विकार के रूप में निदान किया था, एफएचसी रिकॉर्ड ने यह संकेत नहीं दिया कि रोगी इस तरह से पीड़ित था। मानसिक विकलांगता के कारण वह अपने द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ हो गया, 'एफएचसी आई हाई कोर्ट ने आगे कहा कि यह इंगित करने के लिए कोई सबूत नहीं था कि अपीलकर्ता 1985 के बाद मानसिक बीमारी से पीड़ित था। उच्च न्यायालय, हमारी राय में, सही है निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता कथित घटना की तारीख पर कार्य की प्रकृति और उसके परिणामों को जानने में सक्षम था। हालाँकि उसने अपनी पत्नी की बेरहमी से और बेरहमी से हत्या कर दी थी, लेकिन उसने बच्चे को कोई चोट या परेशानी नहीं पहुँचाई। बल्कि उसने यह सुनिश्चित करने का मन बना लिया कि हत्या के बाद बच्चे को उचित देखभाल और संरक्षण में रखा जाएगा। घटना से पहले और बाद में अपीलकर्ता का आचरण किसी भी धारणा को नकारने के लिए पर्याप्त था कि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त था, इसलिए उसके पास अपनी पत्नी की हत्या करने के लिए आवश्यक मानसिक सुरक्षा नहीं थी।

22. इस मामले को देखते हुए, हमें नीचे की अदालतों द्वारा दर्ज किए गए समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है। अपील खारिज की जाती है।”

(31) उपर्युक्त निर्णयों में निर्धारित सिद्धांत के पुनरुत्पादन के बाद, अब स्पष्ट प्रश्न यह है कि क्या वर्तमान अपीलकर्ता भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के प्रावधानों का लाभ पाने का हकदार है या नहीं?

(32) इससे पहले कि हम फिर से, संक्षेप में, ट्रायल कोर्ट के समक्ष इस संबंध में दिए गए सबूतों पर आएं, यहां यह बताना प्रासंगिक होगा कि मानसिक रूप से अस्वस्थता की दलील इस आधार पर ली गई थी कि यह जिला जेल के चिकित्सा अधिकारी थे नारनौल, जिन्होंने राय दी थी कि अपीलकर्ता स्किज़ोफ्रेनिक है और उसे पीजी आई एमएस, रोहतक में भर्ती कराया जाए। उसके बाद उन्हें जिला जेल, रोहतक में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उन्हें अगस्त और सितंबर 2006 में (घटना के दो महीने बाद से) मनोचिकित्सक द्वारा परामर्श दिया गया और उसके बाद, 13.10.2006 को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें छुट्टी दे दी गई। 08.02.2007 को मेडिकल बोर्ड द्वारा उसका निदान करने और लगातार भ्रम विकार से पीड़ित पाए जाने के बाद उसे परीक्षण का सामना करने के लिए फिट घोषित किया गया।

(33) अब यह देखना है कि क्या अपीलकर्ता को "कानूनी रूप से निर्दोष" कहा जा सकता है उसे आईपीसी की धारा 84 का संरक्षण प्रदान करें, घटना के समय उसके व्यवहार के संबंध में अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा दर्ज किए गए साक्ष्य को देखा जाना चाहिए।

एक दलील जो आसानी से उठाई जा सकती है वह यह है कि क्या कोई भी, जो स्वस्थ दिमाग, पत्नी को पीटने,

या अपने जीवनसाथी को सिर पर मारने का सहारा लेगा, और वह भी सुबह के समय, बिना किसी गंभीर उकसावे के; स्पष्ट उत्तर, सामान्य ज्ञान के अनुसार, यह है कि कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। धारा 84 में दिए गए अपवाद का लाभ? हमें नहीं लगता. इस अपवाद की धारा का लाभ उठाने के लिए, यह साबित करना होगा, भले ही अभियोजन पक्ष द्वारा आवश्यक सबूतों की उतनी ताकत पर न हो, लेकिन फिर भी, फिर भी, एक प्रशंसनीय सीमा तक, कि अभियुक्त समझने में असमर्थ था उसके कृत्य की प्रकृति. वर्तमान सहजता में अपीलकर्ता का व्यवहार उसके कार्य की समझ की ऐसी कोई पूर्ण कमी नहीं दर्शाता है, जिससे उसे विकृत दिमाग का करार दिया जा सके, ताकि उसे अपवाद का लाभ दिया जा सके।

पीडब्ल्यू 10, II और 12 के अनुसार जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है, उनके अपने सभी बच्चों के लिए, यहां तक कि घटना की तारीख से पहले भी, मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कोई सबूत नहीं था।

पीडब्लू10, आई.सी. के अनुसार। अपराध के समय बेटी की उम्र लगभग 18-19 वर्ष थी, वह अपने माता-पिता के बीच झगड़े का शोर सुनकर जाग गई और उसने देखा कि उसके पिता उसकी मां को मांडा से वार कर रहे हैं। हालाँकि, जब उसने उससे पूछताछ की, तो उसने उसे चुप रहने के लिए कहा और उसे पीटने की धमकी दी। उसके शोर मचाने पर उसने फिर से उसके (अपनी पत्नी के) सिर पर डंडा मारा और उसके बाद मौके से भाग गया। 'यही संस्करण पीडब्लू12 द्वारा दिया गया है, जो 17-18 वर्ष का था, और उसी कमरे में सो रहा था। पीडब्लू11, यानी सबसे बड़ा बेटा, जो पीडब्लू 10 से थोड़ा बड़ा है, ने यह भी कहा कि जब वह पहुंचा तो उसने अपने पिता को अपनी बहन के बुलाए जाने के बाद भागते हुए देखा। यह भी कहा जाता है कि दाह संस्कार के समय उन्होंने अपने बच्चों को धमकी दी थी (हालांकि गवाही की वह बाल्टी संदेह के घेरे में है, जैसा कि पहले चर्चा की गई थी)। मुझे पता है, किसी भी मामले में, अपनी बेटी को दी गई धमकी को देखते हुए और अपराध को अंजाम देने के बाद उसके भाग जाने से स्पष्ट रूप से उसे अपने कृत्य के बारे में पता था।

पीडब्लू 8 और 9 (दोनों का नाम राम चंदर है), पहला एक रिश्तेदार था जिसे घटना के बारे में PW11 द्वारा सूचित किया गया था और उसके बाद वह अपने ही गाँव से आया था, और बाद में गाँव का लम्बरदार और एक पूर्व रक्षा कर्मी था, दोनों ने अपीलकर्ता की किसी भी मानसिक अस्वस्थता के संबंध में अनभिज्ञता व्यक्त की। जाहिर है, किसी ने भी अपीलकर्ता को ऐसी मानसिक स्थिति में नहीं देखा था, जिसे अस्वस्थ या जानने में असमर्थ माना जा सकता है उसके कार्यों के परिणामों को जानना।

(34) अब मैं फिर से उस पर आता हूं जो मी नॉटेन नियमों में तैयार किया गया है, जैसा कि सुधाकरन की आसानी (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में संदर्भित है, संबंधित भाग मी नॉटन मामले में दिए गए प्रश्न और उत्तर, जैसा कि इस निर्णय में पहले पुन: प्रस्तुत किया गया है, इस प्रकार हैं: -

प्रश्न का उत्तर (i) "हमारा मानना है कि पार्टी ने इसके बावजूद एक विचार के साथ शिकायत की थी। किसी कल्पित शिकायत या चोट के निवारण या प्रतिशोध का प्रभाव, या 'कुछ सार्वजनिक लाभ उत्पन्न करने का प्रभाव,

फिर भी वह अपराध की प्रकृति के अनुसार दंडनीय है, यदि वह जानता था, ऐसे अपराध करने के समय , कि वह देश के कानून के विपरीत काम कर रहा था।

प्रश्न संख्या 4. यदि कोई व्यक्ति मौजूदा तथ्यों के बारे में पागल भ्रम में है और उसके परिणामस्वरूप अपराध करता है, तो क्या उसे माफ कर दिया जाएगा?

उत्तर: उत्तर अवश्य देना चाहिए बेशक, भ्रम की प्रकृति पर निर्भर करता है, लेकिन वही धारणा बनाते हुए जैसा कि हमने पहले किया था, कि वह केवल इस तरह के आंशिक भ्रम के तहत काम करता है और अन्य मामलों में पागल नहीं है, हमें लगता है कि जिम्मेदारी के मामले में उसे उसी स्थिति में माना जाना चाहिए यदि जिन तथ्यों के संबंध में भ्रम मौजूद है वे वास्तविक थे। उदाहरण के लिए, यदि, अपने भ्रम के प्रभाव में, वह मानता है कि कोई अन्य व्यक्ति उसके जीवन को छीनने का प्रयास कर रहा है, और वह उस व्यक्ति को मार देता है, जैसा कि वह आत्मरक्षा में मानता है, तो उसे सजा से छूट दी जाएगी। यदि उसके भ्रम से यह पता चलता है कि मृतक ने उसके चरित्र या भाग्य को गंभीर चोट पहुंचाई है, और उसने ऐसी कथित चोट का बदला लेने के लिए उसे मार डाला, तो वह दंड का भागी होगा।

(35). साक्ष्य ऐसा कोई संकेत नहीं है, कि मृतक, जो अपीलकर्ताओं की पत्नी थी, किसी भी समय, उसे धमकी देने की स्थिति में थी जिससे उसे विश्वास हो कि वह आत्मरक्षा में कार्य कर रहा था; दरअसल, सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपने बयान में भी उन्होंने ऐसी कोई दलील नहीं दी थी। जिसे परीक्षण के लिए फिट घोषित किए जाने के बाद दर्ज किया गया था। इसलिए, भले ही वह अपराध करते समय किसी भ्रम में था कि उसने उसके चरित्र या भाग्य को किसी प्रकार की चोट पहुंचाई है, या किसी भी तरह से उसके प्रति दयालु नहीं थी, फिर भी, परिणामों के बारे में जानते हुए अपने कृत्य के लिए, यहां तक कि मेरे गैर-नियमों के अनुसार भी, वह दंड का भागी होगा।

इस प्रकार, चर्चा किए गए कानून के अनुसार, लाभ लेने के लिए उसे अपने कृत्य की प्रकृति को समझने में पूरी तरह से असमर्थ दिखाना होगा। धारा 84 आई पीसी की ट्रायल कोर्ट में पेश किए गए सबूतों के अनुसार, हमारी दृढ़ राय है कि वह ऐसी किसी भी मानसिक स्थिति में नहीं था।

(36) हालांकि, एक बिंदु पर, हम इस मामले को फिर से पीजीआई में चिकित्सा विशेषज्ञों के पास भेजने के इच्छुक थे। चंडीगढ़, इस तरह के निर्देश की निरर्थकता स्पष्ट हो गई और इसलिए हम पहले से ही हमारे सामने मौजूद चिकित्सा और अन्य सबूतों के आधार पर मामले को आगे बढ़ाने लगे। हम 'निरर्थकता' कहते हैं, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कोई भी निदान, अब घटना के 6 साल बाद और उसके जेल में इतना समय बिताने के बाद, संभवतः 17/18.06 की रात को उसकी मानसिक स्थिति का सटीक वर्णन नहीं कर सकता है। 2006 अगस्त 2006 से फरवरी 2007 तक के महीनों में अपीलकर्ता का अवलोकन करने के बाद पीजी1एमएस, रोहतक द्वारा पहले ही दिए गए निदान का हवाला देकर हम उस समय के सबसे करीब पहुंच सकते हैं। उसी के आधार

पर, डीडब्ल्यूआई डॉ. आईएलसीएच खुराना, मनोरोग विभाग, पीजीआईएमएस, रोहतक की गवाही को फिर से संदर्भित किया जा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह सटीक रूप से बताना संभव नहीं है कि प्रारंभिक समस्या कब उत्पन्न हुई या यह कब शुरू हुई।

(37) इसलिए, पूरे साक्ष्य की सराहना करने के बाद, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलकर्ता धारा 302 आई पीसी के तहत अपनी पत्नी की हत्या करने का दोषी है और वह अपवाद के बचाव का लाभ लेने का हकदार नहीं है: बशर्ते कि उसकी धारा 84।

इस प्रकार, धारा 300 आई पीसी के खंड iv के तहत आने वाले अपराध के लिए, धारा 302 आई पीसी के तहत उसकी सजा को बरकरार रखते हुए, इस अपील को खारिज कर दिया गया है। परिणामस्वरूप, दी गई 'आजीवन कारावास' की सज़ा भी बरकरार रखी जाती है।

जे.एस. मेहंदीरत्ता

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उदेश्य के लिए इसके उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उदेशयों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य के लिए उपयुक्त होगा।

सरू गोयल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

पानीपत, हरियाणा